साप्ताहिक हिन्दी और उर्दू समाचार पत्र

जयपुर से प्रकाशित

उम्मीद की एक नई रोशनी

आवाज़ ए तसनीम

tasneemtv.official@gmail.com

آوازِ تسنیم

PRGI No. RJBIL/25/A1815

www.tasneemtv.com | अंकः 22 / वर्षः 01 | जयपुर, सोमवार, 15 दिसंबर, 2025 | पृष्ठः 8 | मूल्यः 2 रूपए | प्रातः कालीन

त्योहार मना रहे यहूदियों पर हमला

शूटर समेत 12 की मौत, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घटना की निंदा की

आवाज़ ए तसनीम

सिडनी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में प्रसिद्ध बोंडी समुद्र तट पर त्योहार मना रहे यहूदियों पर दो बंदूकधारियों द्वारा की गई अंधाधुंध फायरिंग में कम से कम 11 लोगों की मौत हुई है। दो पुलिस अधिकारियों समेत 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दो हमलावरों में से एक को मार गिराया है, जबकि दूसरा हमलावर पकड़ा गया है और गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने एक हमलावर की पहचान की है। हमलावर की पहचान 24 वर्षीय नवीद अकरम के रूप में हुई जो सिडनी का रहने वाला है। पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा है।प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने इस घटना को स्तब्धकारी और दुखद बताया है। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हुई गोलीबारी को आतंकवादी हमला घोषित किया गया है।

पुलिस ने एक हमलावर समेत 10 लोगों की मौत की पुष्टि की है। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के अनुसार, यह गोलीबारी आठ दिवसीय यहूदी त्योहार हनुक्का की पहली रात को हुई। बंदूकधारियों ने उस वक्त गोलीबारी शुरू कर दी, जब यहूदी त्योहार की शुरुआत के उपलक्ष्य में समुद्र तट पर आयोजित एक कार्यक्रम के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए थे। एक चश्मदीद ने बताया कि हमलावरों ने बच्चों और बुजुर्गों को अंधाधुंध निशाना बनाया। एक अन्य चश्मदीद ने बताया कि उसने कम से कम 10 लोगों को जमीन पर पड़े देखा और हर जगह खून बिखरा हुआ था।

हमले से जुड़े वीडियो वायरल

इस हमले से जुड़े कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इनमें से एक में समुद्र तट और पास में मौजूद लोग गोलियों की तड़तड़ाहट और पुलिस वाहनों के सायरन की आवाज सुनकर इधर-उधर भागते दिखाई दे रहे हैं। एक वीडियो में काले रंग की कमीज पहने एक व्यक्ति को बड़ी बंदूक चलाते हुए देखा जा सकता है, जिसके बाद सफेद टी-शर्ट पहने एक अन्य व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया और उससे बंदूक छीन ली। एक अन्य व्यक्ति को पैदल यात्री पुल से बंदूक चलाते हुए देखा गया। एक अन्य वीडियो में वर्दीधारी पुलिसकर्मी एक छोटे पैदल यात्री पुल पर दो पुरुषों को जमीन पर दबाते नजर आ रहे हैं। पुलिसकर्मी इनमें से एक को होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं.

पीएम मोदी बोले

आज ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर यहूदी त्योहार हनुक्का के पहले दिन जश्न मना रहे लोगों को निशाना बनाकर किए गए भयानक आतंकवादी हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। भारत के लोगों की ओर से मैं उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। दुख की इस घड़ी में हम ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ खड़े हैं। भारत आतंकवाद के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस रखता है और आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करता है।

पीएम अल्बनीज बोले: हमले के बाद देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि यहूदी लोगों पर किया गया हमला, हर ऑस्ट्रेलियाई नागरिक पर किया गया हमला है। आज रात हर ऑस्ट्रेलियाई मेरी तरह ही इस हमले से गहरे सदमे में है। हमारे देश में नफरत, हिंसा और आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि हम इसे पूरी तरह खत्म करेंगे।

घटना की टाइमलाइन

- **शाम 6:45 बजे** — बॉन्डी बीच पर गोलीबारी की खबरों के बाद पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस मौके पर पहुंचीं।
- **शाम 7:05 बजे** — पुलिस ने लोगों को बॉन्डी बीच से दूर रहने का आग्रह किया और घटनास्थल पर मौजूद लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने को कहा।
- **शाम 7:43 बजे** — पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया।
- **रात 8:35 बजे** — एम्बुलेंस 16 घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में ले गईं।
- **रात 8:45 बजे** — पुलिस ने शूटर समेत 12 लोगों की मौत, दो पुलिस अधिकारी सहित 11 अन्य लोग घायल की पुष्टि की।

नोट: ऑस्ट्रेलिया समयानुसार

पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पीयूष गोयल ने किया ऐलान

आवाज़ ए तसनीम

लखनऊ। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को अपना नया अध्यक्ष मिल गया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के निर्विरोध निर्वाचन का ऐलान राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में किया। लखनऊ के लोकभवन में आयोजित समारोह में पंकज चौधरी के हाथों में कमान आने के साथ ही प्रदेश भाजपा में संगठनात्मक स्तर पर एक नए युग का सूत्रपात हो गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय परिषद का निर्वाचन भी हुआ है। पीयूष गोयल ने कहा कि यह घोषित करते हुए खुशी हो रही है कि भाई पंकज चौधरी को सर्वसमिति से चुन लिया गया है। पंकज चौधरी को यूपी भाजपा अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने के साथ ही निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष का प्रमाणपत्र भी दिया गया। इसके साथ ही निर्वतमान अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और पंकज चौधरी की कुर्सी बदली गई। पद संभालते ही सबसे पहले पंकज चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैर छुए।

पीयूष गोयल ने इसके साथ ही 120 राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के निर्वाचन की भी घोषणा की। राष्ट्रीय परिषद सदस्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र सिंह चौधरी, स्मृति ईरानी (सुल्तानपुर), सूर्य प्रताप शाही, रमापति राम त्रिपाठी, महेंद्र नाथ पांडेय भी शामिल हैं। पंकज चौधरी की नियुक्ति को भाजपा का एक बड़ा राजनीतिक दांव माना जा रहा है। वह पूर्वांचल के महाराजगंज से सात बार के अनुभवी सांसद हैं और कुर्मी समुदाय से आते हैं। उनकी इस पद पर ताजपोशी के पीछे पार्टी की गहरी और बहुआयामी रणनीति है। यूपी खासकर पूर्वांचल में ओबीसी आबादी एक बड़ा वोट बैंक है। पंकज चौधरी जैसे मजबूत कुर्मी नेता को कमान सौंपकर भाजपा विपक्ष के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समीकरण की काट करना चाहती है और ओबीसी मतदाताओं पर अपनी पकड़ और मजबत करना चाहती है।

राजस्थान में कोहरे के कारण बस रास्ता भटकी: श्रीगंगानगर में 5 मीटर विजिबिलिटी, 2 दिन में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री बढ़ा

आवाज़ ए तसनीम

जयपुर। राजस्थान में सोमवार सुबह अलवर, श्रीगंगानगर और जैसलमेर में घना कोहरा छाया रहा। अलवर में विजिबिलिटी 20, तो श्रीगंगानगर में 5 मीटर तक रह गई थी। इससे वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। घने कोहरे के कारण जयपुर से श्रीगंगानगर जा रही बस सादुलशहर (श्रीगंगानगर) की सड़क पर चली गई। बाद में ड्राइवर ने बस को वापस मोड़ा।

पश्चिमी विक्षोभ का असर रविवार को कम रहा। बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर संभाग के अधिकांश हिस्सों में इस सिस्टम के असर से हल्के बादल रहे। बादलों के छाने से कई शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट, सर्द हवा कमजोर पड़ने से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई। मौसम केन्द्र जयपुर ने राज्य में अगले 5 दिन मौसम ड्राय रहने का अनुमान जताया है।

पिछले 24 घंटे का मौसम देखें तो जयपुर, सीकर, दौसा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनूं, नागौर, अलवर, अजमेर, बाड़मेर के एरिया में हल्के बादल रहे। इससे इन शहरों में रविवार को धूप थोड़ी कमजोर रही। रविवार को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के एरिया में सुबह 10-11 बजे तक कोहरा रहा।

इस कारण जैसलमेर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस (3 डिग्री गिरावट) पर दर्ज हुआ। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 29.4, जोधपुर में 30.5, बीकानेर में 29, चूरू में 28.3, श्रीगंगानगर में 24.5, उदयपुर में 28, चित्तौड़गढ़ में 28.8, कोटा में 26.7, सीकर में 27, पिलानी (झुंझुनूं) में 27.6, जयपुर, अजमेर में 26.8 और अलवर में 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

रात में कड़ाके की सर्दी से मामूली राहत

बादल छाने से कमजोर हुई उत्तरी हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई। इससे शेखावाटी के एरिया में लोगों को कड़ाके की सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। सीकर, फतेहपुर, चूरू, झुंझुनूं, पिलानी (झुंझुनूं) के एरिया में पिछले 2 दिन में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। रविवार को फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस, सीकर में 9, पिलानी में 9.6 और चूरू में 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

करौली में न्यूनतम तापमान 7.2, दौसा में 7.8, लूणकरणसर में 6.9, पाली में 9.9, बारां में 8.6, नागौर में 7, जालोर में 8.7, उदयपुर में 9.6, चित्तौड़गढ़ में 9.3, अलवर में 7.5 और वनस्थली (टोंक), भीलवाड़ा में 9-9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

राज कुमार गोयल होंगे देश के मुख्य सूचना आयुक्त

> राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज दिलाएंगी पद और गोपनीयता की शपथ

आवाज़ ए तसनीम

नई दिल्ली। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राज कुमार गोयल देश के अगले मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) होंगे। सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय पैनल ने गोयल के नाम की सिफारिश की थी।

गोयल अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-यूनियन टेरिटरी (एजीएमयूटी) कैडर के 1990 बैच के आइएएस अधिकारी हैं। वे इसी साल 31 अगस्त को कानून और न्याय मंत्रालय के अधीन न्याय विभाग के सचिव के पद से सेवानिवृत हुए थे। उन्होंने गृह मंत्रालय में सचिव (सीमा प्रबंधन) के रूप में भी कार्य किया। वे केंद्र और जम्मू और कश्मीर में महत्वपूर्ण पदों पर रहे।

सीआईसी का पद हीरालाल समरिया के 13 सितंबर को कार्यकाल पूरा करने के बाद से खाली पड़ा हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय पैनल ने बुधवार को हुई बैठक में केंद्रीय सूचना आयोग में आठ सूचना आयुक्तों (आईसी) के नामों की भी सिफारिश की।

हमारे सामने एस-400, राफेल कुछ भी नहीं, लश्कर आतंकी ने उगला जहर

दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे

आवाज़ ए तसनीम

इस्लामाबाद। दुनियाभर में आतंकवाद फैलाने के लिए कुख्यात पाकिस्तान की एक बार फिर से पोल खुल गई है। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अब्दुल रऊफ का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। इस वीडियो में वह कहता है कि दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे और हमारे सामने एस-400 और राफेल कुछ भी नहीं हैं। रऊफ कुख्यात आतंकी और लश्कर प्रमुख हाफिज सईद का काफी करीबी है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकियों की कब्र पर कलमा पढ़ता दिखाई दिया था। इस दौरान पाकिस्तानी सेना के भी कई अधिकारी मौजूद थे। इंडिया टुडे के अनुसार, रऊफ ने अपने भड़काऊ वीडियो में कहा है कि कश्मीर में युद्ध खत्म नहीं हुआ है और जो लोग ऐसा सोचते हैं, वह गलत है। उसने कहा कि कश्मीर में हिंसा जारी रहने वाली है। हाफिज सईद के बहनोई अब्दुल रहमान मक्की को कोट करते हुए रऊफ ने कहा कि आतंकी संगठन का का अभी भी मकसद भारत की राजधानी पर कब्जा करना है। अपने वीडियो में रऊफ ने भारतीय सेना पर भी जहर उगला। उसने राफेल विमान, एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन जैसे हथियारों को बेकार बताया है। उसने कहा कि यह सब हमारे सामने कुछ भी नहीं हैं। वह कहता है कि भारतीय वायुसेना पाकिस्तानी एयरस्पेस में अब नहीं घुसने की हिम्मत करेगी। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है।

अपहरण, दुष्कर्म और हत्यारोपी की राष्ट्रपति ने खारिज की दया याचिका

> 2 साल की बच्ची से रेप के बाद की थी हत्या, दरिंदे को मिली सजा-ए-मौत

आवाज़ ए तसनीम

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में 2012 में दो साल की बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के दोषी व्यक्ति की दया याचिका खारिज कर दी है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। राष्ट्रपति पद पर 25 जुलाई, 2022 को आसीन होने के बाद मुर्मू की ओर से खारिज की गई यह तीसरी दया याचिका है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर, 2019 को रवि अशोक घुमारे को दी गई मौत की सजा को बरकरार रखी। अदालत ने कहा कि उसका अपनी कामुक इच्छाओं पर कोई नियंत्रण नहीं था और उसने अपनी यौन भूख को शांत करने के लिए सभी प्राकृतिक, सामाजिक और कानूनी सीमाओं को तार-तार कर दिया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत (जो अब प्रधान न्यायाधीश हैं) की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने दो अनुपात एक के बहुमत से यह फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि उस व्यक्ति ने एक ऐसे जीवन को निर्दयतापूर्वक समाप्त कर दिया जो अभी खिलना बाकी था। 2 वर्षीय बच्ची से अप्राकृतिक अपराध करने का उसका कृत्य एक गंदी और विकृत मानसिकता को दर्शाता है, जो क्रूरता की एक भयावह कहानी को प्रदर्शित करता है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी की गई दया याचिका की स्थिति के अनुसार, रवि अशोक घुमारे की दया याचिका राष्ट्रपति ने 6 नवंबर, 2025 को खारिज की। अधीनस्थ अदालत ने घुमारे को दोषी ठहराते हुए 16 सितंबर, 2015 को मौत की सजा सुनाई थी।

बाल-बाल बचे मंत्री अनिल विज

अंबाला/ एजेंसी। हरियाणा के परिवहन और बिजली मंत्री अनिल विज रविवार को बाल-बाल बच गए। एक वाहन ने उनके सुरक्षा काफिले के बीच घुसकर सीधे उसकी कार को जोरदार टक्कर मारी। यह हादसा पड़ाव क्षेत्र में हुआ है। मंत्री अनिल विज के आगे और पीछे सुरक्षा वाहनों का काफिला चल रहा था, लेकिन एक काले रंग की गाड़ी ने सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए सीधे मंत्री की कार को निशाना बनाया। गनीमत रही कि मंत्री अनिल विज को कोई चोट नहीं आई और वह पूरी तरह सुरक्षित हैं। इस बीच काफिले में सवार पुलिसकर्मी तुरंत अलर्ट हो गई और कमांडो ने गाड़ी को घेर लिया।

बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नबीन

पटना/ एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर बड़ा फैसला लेते हुए बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन (45) को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस नियुक्ति को बिहार के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी की रणनीतिक मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी नेतृत्व ने उनके संगठनात्मक अनुभव, जमीनी पकड़ और प्रशासनिक क्षमता को देखते हुए यह अहम जिम्मेदारी सौंपी है। नितिन नबीन बीजेपी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने हैं। यह नियुक्ति 14 दिसंबर 2025 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इस संबंध में पार्टी की ओर से औपचारिक संगठनात्मक आदेश जारी किया गया है।

जयपुर में पकड़े गए 2.90 लाख के नकली नोट

उत्तर प्रदेश से लाए थे नोटों की खेप, पुलिस ने दबिश देकर 2 तस्करों को पकड़ा

आवाज़ ए तसनीम

जयपुर। जयपुर कमिश्नरेट की सीएसटी ने रविवार रात दबिश देकर नोट तस्करी में दो बदमाशों को अरेस्ट किया है। चित्रकूट इलाके से पकड़े दोनों बदमाशों से 2.90 लाख रुपए के नकली नोट मिले हैं। पूछताछ में आरोपियों ने नकली नोटों की खेप उत्तर प्रदेश से लेकर आना बताया है।

स्पेशल कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताया- नकली नोट तस्करी में बदमाश गोविंद चौधरी निवासी झालावाड़ और देवांश फांडा निवासी चित्रकूट नगर वैशाली नगर को अरेस्ट किया है। सीएसटी के इंस्पेक्टर रतन सिंह की टीम को सूचना मिली की चित्रकूट इलाके में एक युवक कार में घूम रहा है, जिसके पास नकली नोट हैं। सीएसटी ने सूचना पर संदिग्ध कार को चित्रकूट इलाके में पकड़ लिया। कार सवार की तलाशी लेने पर उसके पास नकली नोट मिले। पुलिस ने आरोपी कार सवार गोविंद को राउंडअप कर उसके पास मिले 1.90 लाख रुपए के नकली नोट जब्त किए।

गोविंद से पूछताछ में उसके साथी देवांश के पास भी नकली नोट होना सामने आया है। सीएसटी टीम ने चित्रकूट इलाके में स्थित देवांश के फ्लैट पर दबिश दी। देवांश को पकड़ उसके कब्जे से 1 लाख रुपए के नकली नोट मिले। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अरेस्ट किया। जिनके कब्जे से मिले 2.90 लाख रुपए के नकली नोट जब्त किए गए। पूछताछ में सामने आया कि नकली नोटों की खेप सहारपुर उत्तर प्रदेश से लेकर आए थे। गिरोह के शामिल बदमाशों के बारे में पूछताछ की जा रही है।

69000 शिक्षक भर्ती मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई

लखनऊ/ एजेंसी। 69000 शिक्षक भर्ती मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होनी है। इसकी कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। 18 नवंबर को इस मामले में लगभग एक घंटे तक सुनवाई हुई थी। सुनवाई शुरू होने से अभ्यर्थियों को जल्द समाधान की उम्मीद है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सरकार पर आरोप लगाया कि बेसिक शिक्षा विभाग कोर्ट में जवाब देने से भाग रहा है। इस मुद्दे पर कोई सक्रियता नहीं दिखा रहा है। अभ्यर्थी पिछले लगभग पांच साल से इस मामले में लड़ रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार इस प्रकरण का निस्तारण तीन माह में करना था जो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। इससे अभ्यर्थियों में असंतोष बढ़ रहा है। अभ्यर्थियों के नेतृत्वकर्ता अमरेंद्र पटेल ने कहा कि सरकार के अधिवक्ता 16 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में अपना पक्ष रखे।

प्रियंका गांधी की बीजेपी को ललकार, वोट चोरी के आरोप के बीच रामलीला मैदान में हुंकार

बैलेट पेपर पर चुनाव लड़ो

एजेंसी

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए चुनावी प्रक्रिया में वोट चोरी और अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को कुचल दिया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को बैलेट पेपर पर चुनाव लड़ने की चुनौती दी। रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोर, गद्दी छोड़ रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि जब हम हर संस्था को कुचलते हुए देखते हैं, तो सभी भारतीयों को इसके खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की सभी संस्थाओं को सरकार के सामने झुकने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

चुनाव प्रक्रिया को निशाना बनाते हुए उन्होंने दावा किया कि हर स्तर पर संदेह है। चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव ठीक से नहीं कराए जा रहे हैं, हर कदम पर संदेह है। उन्होंने आगे पूछा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान 10000 रुपये के भुगतान पर चुनाव आयोग ने आंखें मूंद लीं; क्या यह वोट चोरी नहीं है? प्रियंका ने भाजपा को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बिना चुनाव लड़ने की चुनौती भी दी। बिहार के हालिया चुनावी नतीजों का जिक्र करते हुए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि आपको बिहार में हार से निराश नहीं होना चाहिए, पूरा देश जानता है कि भाजपा वोटों की चोरी के जरिए जीत हासिल करती है। संसद सत्रों के बारे में बात करते हुए प्रियंका ने कहा कि चुनावी मुद्दों पर बहस की विपक्ष की मांग का विरोध किया गया।

> मैं भाजपा को मतपत्र पर चुनाव लड़ने की चुनौती देती हूं, वे जानते हैं कि वे कभी नहीं जीतेंगे। मैं उन्हें निष्पक्ष चुनाव लड़ने की चुनौती देती हूं। उन्हें मतपत्र पर चुनाव लड़ने दीजिए, वे खुद जानते हैं कि वे कभी नहीं जीतेंगे।
>
> **प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस सांसद**

त्रिशूर में टूटा सियासी मिथक, BJP की मुस्लिम उम्मीदवार ने कांग्रेस से छीनी सीट

अवाज़ ए तसनीम

केरल की सियासत में बीजेपी की मजबूत एंट्री ने जानकारों को हैरान कर दिया. त्रिशूर नगर निगम चुनाव में बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवार ने ऐतिहास जीत हासिल की. बीजेपी प्रत्याशी मुमताज ने त्रिसूर की हिंदू बहुल सीट पर जीत हासिल की है, जिस पर 28 हिंदू उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे थे. कन्ननकनगरा वार्ड को परंपरागत रूप से हिंदू बहुल क्षेत्र माना जाता रहा है. ऐसे में इस वार्ड से बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवार की जीत को सियासी जानकार एक नए सामाजिक समीकरण के रूप में देख रहे हैं. त्रिसूर नगर निगम में बीजेपी की इस जीत को लेकर स्थानीय सियासत में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.मिली जानकारी के मुताबिक, त्रिसूर नगर निगम चुनाव में बीजेपी की ओर से मुमताज अकेली मुस्लिम उम्मीदवार थीं. मुमताज पिछले आठ सालों से बीजेपी से जुड़ी हुई हैं. इतना ही नहीं उनका परिवार भी लंबे समय से पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक के रूप में सक्रिय रहा है. बीते दो सालों के दौरान पार्टी ने उन्हें अपने अल्पसंख्यक मोर्चा की जिम्मेदारी भी सौंपी थी. जहां उनका कार्यक्षेत्र स्थानीय इलाकों तक सीमित रहा है.मुमताज पेशे से बिजनेसवुमैन हैं और वह त्रिसूर में पालतू जानवरों की एक दुकान चलाती हैं. चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इसे शहर की सेवा करने का मौका बताया. इससे पहले मुमताज कह चुकी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और विकास की सोच से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी से जुड़ने का फैसला किया था. उन्होंने पार्टी की कई चुनावी अभियानों और रैलियों में सक्रिय रूप से भाग लिया है.मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुमताज एक्टर से नेता बने सुरेश गोपी के अगुवाई में चलाए गए चुनावी प्रचार अभियान में भी शामिल रही हैं. कन्ननकनगरा वार्ड में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार सिंधु चकुलैयिल को हराकर जीत दर्ज की. गौर करने वाली बात यह भी है कि इस साल त्रिसूर नगर निगम चुनाव में महिलाओं की भागीदारी को लेकर भी काफी चर्चा रही. इस सीट से कुल 28 महिला उम्मीदवारों ने चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाई.चुनाव जीतने के बाद मुमताज ने कहा कि वह पिछले आठ सालों से पार्टी के लिए लगातार काम कर रही हैं. मुमताज मुताबिक पार्टी ने उन पर भरोसा जताया क्योंकि उन्हें लगा कि वह आम लोगों तक आसानी से पहुंच बना सकती हैं. उन्होंने कहा कि चाहे उनका बिजनेस हो या निजी जिंदगी, वह समाज से जुड़कर सक्रिय रूप से काम करती रही हैं और आगे भी इसी तरह जनता की सेवा करती रहेंगी.यह भी पढ़ेंः शांति के ठेकेदार अमेरिका में नफरत का नंगा नाच, वर्जीनिया में मस्जिद से लौट रही मुस्लिम औरतों पर जानलेवा हमला

नबी (स.अ.) की तौहीन पर नकेल की तैयारी; MCOCA-UAPA का प्रस्ताव के विधानसभा पहुंचे

संवाद अपडेट

महाराष्ट्र हालिया दिनों असामाजिक तत्व लगातार नबी (स.अ.) के खिलाफ विवादास्पद और आपत्तिजनक बयानों के मामले बढ़ गए हैं. इस तरह के नफरती, अपमानित करने और धार्मिक नफरत फैलाने यानी तौहीन-ए-रिसालत पर लगाम लगाने के लिए सपा विधायक अबू आसिम आजमी ने विधानसभा में प्राइवेट बिल पेश किया है. दिल्ली में मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे का उमर अंसारी का शाही रिसेप्शन, ओवैसी-ओसामा समेत पहुंचे कई दिग्गजसपा विधायक अबू आसिम आजमी (फाइल महाराष्ट्र समेत पूरे देश में मुसलानों के खिलाफ नफरत, हिंसा और इस्लाम के आखिरी नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले बढ़ गए हैं. इस तरह के बेलमान तत्वों पर लगाम लाने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी ने एक प्राइवेट बिल पेश किया.इस बिल में अबू आसिम आजमी ने पैगंबर (स.अ.) के अपमान (तौहीन-ए-रिसालत) और धार्मिक नफरत फैलाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग है. इस बिल में कहा गया है कि नफरत फैलाने वाले तत्वों पर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्टऔर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के तहत कार्रवाई की जाए.बिल के मुताबिक, ऐसे मामलों में दोषियों को दस साल तक की सजा दी जाए और दो लाख रुपये की जमानत की शर्त लगाई जाए, ताकि आरोपियों को आसानी से जमानत न मिल सके और धार्मिक नफरत की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके. अबू आसिम आजमी ने सदन को बताया कि देश में नबी (स.अ.) के अपमान और नफरत भरे बयानों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ रहा है और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर असर पड़ रहा है. समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में नफरत का एजेंडा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करना समय की मांग है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों का भी हवाला दिया, जिनमें नफरत भरे भाषण और भड़काऊ बयानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. सपा विधायक ने कहा कि इन्हीं निर्देशों के आधार पर महाराष्ट्र में धार्मिक नफरत फैलाने और महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक शख्सियतों के खिलाफ जहर उगलने वालों पर कार्रवाई के लिए यह बिल पेश किया गया है.इंकलाब में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, बिल के मसौदे में यह प्रस्ताव भी शामिल है कि सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ दस साल या उससे अधिक सजा के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया जाए. साथ ही मकोका, यूएपीए जैसे कड़े कानून लागू किए जाएं ताकि आरोपियों को जमानत न मिल सके. इस दौरान अबू आसिम आजमी ने लाल किले के पास कार बम धमाके की कड़ी निंदा की. उन्होंने इसे सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक और खुफिया तंत्र की नाकामी बताया. उन्होंने कहा कि एक व्यस्त और संवेदनशील इलाके के पास इस तरह की घटना बेहद चिंताजनक है.आजमी ने साल 2006 के मुंबई ट्रेन बम धमाकों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उस समय कई निर्दोष मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने सालों तक जेल की यातनाएं झेलीं और बाद में उन्हें सम्मान के साथ बरी किया गया, लेकिन आज तक असली दोषियों का पता नहीं चल सका.अबू आसिम आजमी ने कहा कि बम धमाके कायरतापूर्ण और इंसानियत के खिलाफ अपराध हैं, जिन्हें किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. उन्होंने मांग की कि ऐसे मामलों में शामिल लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके.

'घर में भी इजाजत लेकर नमाज पढ़ो,' देहरादून में हिंदू संगठनों की खुली धमकी, पुलिस बनी रही मूक दर्शक

अवाज़ ए तसनीम

पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं. बीते शुक्रवार को हिंदू संगठन के लोगों ने जुमे की नमाज पढ़ने से रोकते हुए मुसलमानों के साथ गाली-गलौज करते हुए उन्हें धमकी दी. यह सब हुआ प्रदेश की राजधानी देहरादून में पुलिस के सामने और इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही. मामले में अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है.क्द्गश्ठ्ठश्- दिल्ली में मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे का उमर अंसारी का शाही रिसेप्शन, ओवैसीङ्कओसामा समेत पहुंचे कई दिग्गजदेहरादून में हिंदूवादी संगठन के लोगों ने मुसलमानों को इबादत से रोकदेहरादून में हिंदूवादी संगठन के लोगों ने मुसलमानों को इबादत से रोकउत्तराखंड इस समय मुसलमानों के खिलाफ नफरत की प्रयोगशाल बन गई है. हिंदूवादी संगठन शासन प्रशासन के सामने लगातार बेगुनाह मुसलमानों के साथ मारपीट करते हुए और उन्हें धमकाते हुए नजर आ रहे हैं. कई मामलों में देखा गया है कि हिंदूवादी संगठनों के गैर-कानूनी गतिविधियों के सामने शासन प्रशासन भी चुप नजर आता है. हिंदूवादी संगठनों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अब इस तरह की घटनाएं राजधानी देहरादून में दिन दहाड़े कैमरे के सामने हो रही हैं, जहां मुसलमानों को अपमानित करने, इबादत करने से रोकते हुए और हिंसा की वारदात को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के मियावाला इलाके में 12 दिसंबर को हिंदूवादी संगठनों ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की कोशिश की. मियावाला इलाके में हिंदूवादी संगठनों ने शुक्रवार को मुसलमानों को जुमे की नमाज अदा पहुंचे मुसलमानों को रोक दिया और मौके पर गाली-गलौज, धमकी देते हुए जमकर हंगामा किया. इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. बताया जा रहा है कि देहरादून के मियावाला इलाके में पुलिस और कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों ने मौके पर पहुंच कर हंगामा शुरू कर दिया. हिंदूवादी संगठन के लोगों मौके पर नमाज पढ़ने पर आपत्ति जताई और नमाज अदा करने के लिए पहुंचे लोगों धमकी दी. वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि हिंदूवादी संगठन के लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ÷वह मुसलमानों को उत्तराखंड में कहीं भी नमाज नहीं पढ़ने देंगे.÷ प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, समूह के लोगों ने न सिर्फ अपशब्दों का इस्तेमाल किया बल्कि यह तक कहा कि अब घर के अंदर नमाज पढ़ने के लिए भी हिंदूवादी संगठनों से इजाजत लेनी होगी. हिंदूवादी संगठन के नेताओं की धमकी के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों में दहशत फैल गई. स्थानीय लोगों ने हिंदूवादी संगठनों के रवैये पर नाराजगी की इजहार किया.वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मुस्लिम परिवार को जब हिंदूवादी संगठन के लोग धमकी दे रहे हैं, उस समय कुछ पुलिस वाले भी मौके पर मौजूद हैं. पीड़ितों को हिंदू संगठन के कार्यकर्ता धमकाते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें नमाज पढ़नी है तो पढ़ो, लेकिन अपने घर में या कहीं भी सामूहिक नमाज पढ़ी तो समस्या खड़ी कर देंगे. मौके पर मौजूद एक पुलिसकर्मी बुजुर्ग मुस्लिम को धमकाता नजर आ रहा है. इस घटना को लेकर अभी तक देहरादून पुलिस प्रशासन का कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है.

भारत के 51 करोड़ वोटर्स शक के दायरे में, SIR ने क्यों बढ़ा दी लोकतंत्र की धड़कन

अवाज़ ए तसनीम

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर देश में राजनीतिक उहापोह और आशंका के बीच खाई गहराती जा रही है. एक ओर चुनाव आयोग इसे तकनीकी सुधार बता रहा है. जबकि बीजेपी के कई नेता हालिया दिनों अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में घुसपैठ पर प्रहार का दावा करते हुए उपलब्धि के तौर पर पेश कर रह हैं. वहीं विपक्ष, सामाजिक संगठन और अल्पसंख्यक समुदाय इसे मताधिकार और लोकतंत्र से जुड़ा गंभीर खतरा मान रहे हैं.भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चलाई जा रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को लेकर देशभर में बहस तेज हो गई है. सरकार और चुनाव आयोग जहां इसे मतदाता सूची को दुरुस्त करने की नियमित प्रक्रिया बता रहे हैं, वहीं विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने इसके जरिए ह्रश्वष्ट जैसे कदम उठाए जाने की आशंका जताई है. इस सियासी टकराव के बीच आम लोगों में, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय में बेचैनी बढ़ती दिख रही है. SIR प्रक्रिया 2025 में चरणबद्ध तरीके से लागू की गई. चुनाव आयोग के मुताबिक, इसका मकसद मतदाता सूची से मृत, स्थानांतरित, डुप्लिकेट और अयोग्य नामों को हटाना है ताकि 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची को अपडेट किया जा सके. आयोग का दावा है कि यह पूरी तरह प्रशासनिक प्रक्रिया है और इसका नागरिकता निर्धारण से कोई ताल्लुक नहीं है.हालांकि, इस प्रक्रिया का दायरा और पैमाना कई सवाल खड़े कर रहा है. स्ठ्ठक्र पहले चरण में जून- जुलाई 2025 के दौरान बिहार में पूरा किया गया. इसके बाद नवंबर-दिसंबर 2025 में इसे दूसरे चरण के तहत 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया. इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 51 करोड़ मतदाताओं की जानकारी दोबारा सत्यापित की जा रही है.चुनाव आयोग के ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक, दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुदुच्चेरी, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह शामिल हैं. कई राज्यों में स्ठ्ठक्र की समयसीमा दिसंबर 2025 तक बढ़ाई गई, जबकि कुछ जगहों पर विशेष पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए हैं.स्ठ्ठक्र के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आंकड़े सामने आए हैं. पश्चिम बंगाल में ड्राफ्ट सूची के मुताबिक करीब 58.08 लाख नाम हटाए गए. इनमें 24.18 लाख मृत मतदाता और करीब 34 लाख लापता या स्थानांतरित बताए गए हैं. सबसे ज्यादा नाम दक्षिण 24 परगना जिले में हटाए गए.बिहार में स्ठ्ठक्र के पहले चरण के दौरान ड्राफ्ट स्तर पर 65 लाख नाम हटाए गए थे, बाद में 3.66 लाख और नाम जोड़े गए. इस तरह कुल 62 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम सूची से बाहर किए गए. अंतिम सूची में बिहार में 7.42 करोड़ मतदाता दर्ज किए गए.उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा और बड़ा है. यहां करीब 2.93 करोड़ मतदाताओं के नाम जांच के दायरे में आए हैं. आयोग के मुताबिक, लगभग 19 फीसदी मतदाताओं ने समय पर जरुरी फॉर्म जमा नहीं किया, जिसके चलते उनके नाम ड्राफ्ट स्तर पर संदिग्ध श्रेणी में रखे गए हैं. आयोग का कहना है कि दावा और आपत्ति की प्रक्रिया के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी.स्ठ्ठक्र के साथ विदेशी नागरिकों की पहचान का मुद्दा भी चर्चा में है. चुनाव आयोग के मुताबिक, बिहार में कुल 390 विदेशी नागरिक चिन्हित किए गए, जिनमें से 76 मुस्लिम थे. इन सभी के नाम अंतिम मतदाता सूची से हटा दिए गए. अन्य राज्यों में विदेशी नागरिकों के मामले बेहद सीमित बताए गए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा आंकड़ा सामने नहीं आया है.इन आंकड़ों के बीच विपक्षी दलों का कहना है कि स्ठ्ठक्र के जरिए वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जा रहे हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है. समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि स्ठ्ठक्र के बहाने ह्रश्वष्ट लागू करने की कोशिश की जा रही है.तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में लाखों मतदाताओं के नाम चुपचाप हटाए जा रहे हैं. कांग्रेस ने इस पूरी प्रक्रिया को गैरकानूनी बताते हुए चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए हैं. वहीं, भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि विपक्ष चुनावी हार के डर से भ्रम फैला रहा है.स्ठ्ठक्रको लेकर आम लोगों की चिंता का एक बड़ी वजह यह भी है कि प्रक्रिया में घर-घर सत्यापन, नए फॉर्म और दस्तावेजों की मांग की जा रही है. खासकर गरीब, मजदूर, किरायेदार और प्रवासी समुदायों में यह आशंका है कि दस्तावेजों की कमी के चलते उनके नाम मतदाता सूची से हट सकते हैं. अल्पसंख्यक समाज में भी इस प्रक्रिया को लेकर विशेष चिंता देखी जा रही है. सामाजिक संगठनों का कहना है कि पहले भी पहचान और दस्तावेजों से जुड़ी प्रक्रियाओं का असर इन्हीं समुदायों पर ज्यादा पड़ा है, इसलिए स्ठ्ठक्र को लेकर आशंकाएं स्वाभाविक हैं.इस प्रक्रिया के दौरान चुनाव कर्मियों पर बढ़ते दबाव का मुद्दा भी सामने आया है. अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, छह राज्यों में कम से कम 33 से 41 बूथ लेवल ऑफिसर्स (क्चरुह्र) की मौतें हुई हैं. इन मौतों को अत्यधिक काम का दबाव, लेट वर्किंग ऑवर और मानसिक तनाव से जोड़ा जा रहा है. इसके बाद चुनाव आयोग ने कुछ राज्यों में समयसीमा बढ़ाने जैसे कदम उठाए हैं.चुनाव आयोग का कहना है कि स्ठ्ठक्र पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया है और किसी भी मतदाता का नाम बिना वजह नहीं हटाया जाएगा. आयोग के मुताबिक, दावा और आपत्ति की प्रक्रिया के जरिए गलत तरीके से हटाए गए नामों को फिर से जोड़ा जा सकता है. केंद्र और 14 राज्यों में बीजेपी अपने बलबूते सत्ता में काबिज है और स्ठ्ठक्रको जिस तरह वह अपनी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है, उससे मुसलमानों के मन में दहशत पैदा हो गई है. इसकी वजह है उन्हों प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से टार्गेट करते हुए बीजेपी ने अपने विज्ञापन जारी किए हैं. बीजेपी के आक्रमक रवैये को देखते हुए मुसलमानों में डर, आशंका और भविष्य को लेकर उहापोह की स्थिति पैदा होना लाजमी है. फिलहाल स्ठ्ठक्र को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है. सरकार इसे लोकतंत्र को मजबूत करने की पहल बता रही है, जबकि विपक्ष और सामाजिक संगठन इसे नागरिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर मुद्दा मान रहे हैं. आने वाले दिनों में दावा-आपत्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि स्ठ्ठक्रका असर मतदाता सूची और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर कितना पड़ता है.

इस राज्य में उम्मीद पोर्टल पर सबसे ज्यादा दर्ज हुई वक्फ संपत्तियां; विपक्षा की सरकार से खास अपील

संवाद अपडेट

केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने 6 जून से 6 दिसंबर के बीच देश भर की वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराने का आदेश दिया था. लेकिन अभी भी बहुत से वक्फ संपत्तियां दर्ज नहीं हो पाई हैं. इन 6 महीनों के भीतर देश भर में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराया गया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. दिल्ली में मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे का उमर अंसारी का शाही रिसेप्शन, ओवैसी -ओसामा समेत पहुंचे कई दिग्गज

इस राज्य में उम्मीद पोर्टल पर सबसे ज्यादा दर्ज हुई वक्फ संपत्तियां; विपक्षा की सरकार से खास अपील

वक्फ संशोधन कानून 2025 का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. इस बीच केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने 6 जून से 6 दिसंबर तक उम्मीद पोर्टल पर सभी वक्फ संपत्तियों को दर्ज कराने का आदेश दिया था. वहीं, मुस्लिम उलेमा और विपक्ष के नेता अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू से उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को दर्ज कराने की समय-सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. 6 जून से 6 दिसंबर यानी पूरे 6 महीने के अंदर देश भर में मुस्लिम समाज के लोगों ने बढ़-चढ़कर उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को दर्ज कराया. हालांकि अभी भी बहुत से ऐसे वक्फ संपत्तियां हैं जिन्हें तकनीकी खामियों की वजह से उम्मीद पोर्टल पर दर्ज नहीं किया जा सका है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराया गया है. उत्तर प्रदेश के मुसलमान वक्फ संपत्ति पंजीकरण कराने में देश में पहले स्थान पर हैं. उत्तर प्रदेश में अब तक 92832 वक्फ संपत्तियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा है, जिनमें क्चसुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की 86347 और शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की 6485 संपत्तियों का पंजीकरण कराया गया है. उत्तर प्रदेश शिया वक्फ संपत्ति के पंजीकरण में लखनऊ और सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में बाराबंकी अव्वल केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने 6 जून को उम्मीद पोर्टल पर पंजीकरण कराने का दिया था. उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में लगभग 62,939 वक्फ संपत्तियों उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराया गया. महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में लगभग 58,328 संपत्तियां दर्ज कराया गया है. गौरतलब है कि वक्फ संशोधन कानून 2025 का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. मुस्लिम समाज और विपक्ष के ज्यादातर नेताओं का कहना है कि भाजपा सरकार इस कानून के तहत अल्पसंख्यक मुस्लिम समजा की धार्मिक आज़ादी का हनन कर रही है. साथ ही इस कानून के कई प्रावधानों पर मुस्लिम समाज ने गहरी आपत्ति व्यक्त की

दिनदहाड़े कत्ल से दहल उठी रायबरेली, बेटी के सामने मदरसा टीचर की गोली मारकर हत्या

आवाज़ ए तसनीम

रायबरेली में मदरसा टीचर मुर्तजा हुसैन की दिनदहाड़े हत्या ने जिले में सनसनी फैला दी है. बेटी के सामने हुई इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं, जबकि पुलिस पुरानी रंजिश और अवैध हथियार फैक्ट्री से जुड़े एंगल की जांच कर रही है. यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है. दिल्ली में मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे का उमर अंसारी का शाही रिसेप्शन, ओवैसीङ्कओसामा समेत पहुंचे कई दिग्गज

प्रतीकात्मक एआई तस्वीर

उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में शुक्रवार (12 दिसंबर) को दिनदहाड़े एक मदरसा टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई. इस घटना के बाद मुसलमानों की सुरक्षा और उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. मृतक की टीचर की पहचान 45 साल के मुर्तजा हुसैन के रूप में हुई है.पुलिस के मुताबिक, मदरसा टीचर मुर्तजा हुसैन अपनी नवविवाहित बेटी इशरत जहां को उसके ससुराल से लेकर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे. यह वारदात डीह थाना क्षेत्र में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास हुई. आरोप है कि रास्ते में 6 से 7 हमलावरों ने उनकी बाइक रोक ली. इस दौरान आरोपियों ने मुर्तजा की बेटी के साथ बदसलूकी की और विरोध करने पर मुर्तजा को पिस्टल से सिर में गोली मार दी. गोली लगने से मुर्तजा की मौके पर ही मौत हो गई. गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा होने लगे तो आरोपी मौके से फरार हो गए. मृतक की बेटी इशरत जहां ने पुलिस को बताया कि करीब आधा दर्जन लोगों ने उन्हें घेर लिया और जबरन बाइक रुकवाई. इशरत के मुताबिक, ÷बदमाशों ने पहले मेरे पिता को पीटा, जब मैंने बीच-बचाव किया तो मुझे जमीन पर गिरा दिया और भगा दिया. इसके बाद उन्होंने मेरे पिता के सिर में गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.÷घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. इशरत जहां की तहरीर पर पुलिस ने दो नामजद और तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.टाइम्स ऑफ इंडिया ने मृतक के भतीजे मोहम्मद तौसीफ के हवाले से दावा किया कि हमलावरों को शक था कि मुर्तजा हुसैन ने हाल ही में उनके घर के पास पकड़ी गई ।

Uttarakhand: स्कूल में कलमा पढ़ाने पर बवाल, हिंदूवादी संगठन ने की ये मांग

आवाज़ ए तसनीम

उत्तराखंड के एक प्राइवेट स्कूल में छात्रों से कलमा पढ़ाने का एक कथित वीडियो वायरल होने पर बवाल खड़ा हो गया है. हिंदूवादी संगठन के लोगों ने प्रशासन से इस स्कूल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. उत्तराखंड के बाजपुर क्षेत्र के कौशल्यापुरी के आदर्शनगर मोहल्ले में एक स्कूल में कथित तौर पर कलमा पढ़ाए जाने पर बवाल खड़ा हो गया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि कौशल्यापुरी के एक स्कूल में बच्चों को इस्लामिक कलमा पढ़ाया जा रहा है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हिन्दूवादी संगठन के लोगों ने स्कूल और स्कूल प्रशासन के खिलाफ विरोध किया और एसडीएम को ज्ञापन देकर संचालक के खिलाफ जल्द सख्त कार्रवाई की माँग की.बता दें कि बाजपुर के आदर्शनगर मोहल्ले में संचालित एक निजी स्कूल में प्रार्थना के दौरान हिंदू छात्रों को कलमा पढ़वाने का आरोप लगाया गया था. इस घटना का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में कुछ छात्र अरबी भाषा के शब्दों का उच्चारण करते दिख रहे थे. इसी वीडियो के आधार पर विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा प्रांत मंत्री यशपाल राजहंस ने आपत्ति जताई है.नका कहना है कि छोटी कक्षाओं के हिंदू छात्रों को जबरन कलमा पढ़ाया गया, जो उनकी धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है. वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एसडीएम को शिकायत दर्ज करवाई है. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.वहीं, स्कूल के प्रधानाचार्य गिरीश चंद्र सैनी ने बताया कि स्कूल में हिन्दू 110 बच्चे और 80 मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं. स्कूल में लगभग एक साल से प्रार्थना के समय सभी बच्चों को बिस्मिल्लाह कलमा पढ़ाया जा रहा था. स्कूल में कलमा पढ़ने की वीडियो वायरल होने पर कलमा पढ़ाना बंद कर दिया है.इस मामले पर जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी पीएस रावत ने कहा कि उन्होंने इस घटना की जानकारी मिली है कि एक प्राइवेट स्कूल में कलमा पढ़ाया जा रहा था. इस मामले की जांच करने पर पता चला कि यह प्राइवेट स्कूल मुस्लिम बहुल इलाके में और इस स्कूल में मुस्लिम और हिंदू दोनों समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं. उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति के मुताबिक स्कूल में इस प्रकार का काम गलत है. उन्होंने जानकारी दी कि इस मामले पर संबंधित स्कूल को नोटिस जारी किया गया है. उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मामले पर संबंधित स्कूल के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.

کیرالا میں کانگریس کیلئے خوشخبری

کیرالہ کے بلدیاتی انتخابات نے بائیں بازو کی کمزوری اور کانگریس کی مضبوط واپسی کے آثار دکھادیے ہیں۔نتائج نے بی جے پی کی پیش رفت اور ایل ڈی ایف کے خلاف عوامی ناراضگی کو بھی نمایاں کیا ہے

آوازِتسنیم

کیرالہ میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے جو نتائج سامنے آئے ہیں اگر وہ مستقبل کی سیاست کا کوئی اشارہ ہیں تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ اب وہاں بائیں بازو کی اجارہ داری ختم ہو رہی ہے اور کانگریس کی قیادت والے متحدہ محاذ (یو ڈی ایف) کے برسر اقتدار آنے کے امکانات روشن ہوگئے ہیں۔ کیرالہ کے مقامی انتخابات کے نتائج کو ہلکے میں نہیں لیا جاسکتا۔ ان کی بڑی اہمیت ہے اور یہ اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ وہاں اگلے سال مارچ میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔اس وقت جو نتائج سامنے آئے ہیں اگر یہی رجحان جاری رہا تو پنرئی وجین کی حکومت کا خاتمہ ہوجائے گا اور کانگریس کی قیادت والے متحدہ محاذ کی حکومت بن جائے گی۔لیکن اگر ہم تروانت پورم کے نتیجے پر نظر ڈالیں تو تشویش بھی پیدا ہوتی ہے کیونکہ وہاں کے کارپوریشن میں بی جے پی کو کامیابی ملی ہے۔

کیرالہ میں چھ کارپوریشنوں، 86 میونسپلٹی بلاکوں، 14 ضلع پنچایتوں، 152 بلاک پنچایتوں اور 941 گرام پنچایتوں کیلئے 9 اور 11 دسمبر کو انتخابات ہوئے ہیں۔ جن میں سے کانگریس کی قیادت والے محاذ کو سب سے زیادہ کامیابی ملی ہے۔کانگریس کے سینئر رہنما راہل گاندھی نے نتائج پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک فیصلہ کن مینڈیٹ ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے ریاست کے عوام تبدیلی چاہتے ہیں اور ایک ایسی حکومت چاہتے ہیں جو ان کے مسائل پر توجہ دے، ان کو حل کرنے کی کوشش کرے اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھے۔ انھوں نے مزید کہا کہ ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے مسائل کے تئیں فکرمند ہیں اور ایک شفاف اور عوام کو ترجیح دینے والی حکومت فراہم کرنے کے تئیں پرعزم ہیں۔

تروانت پورم سے کانگریس کے ایم پی اور وقتاً فوقتاً بی جے پی اور وزیر اعظم نریندر مودی کی تعریف کرنے والے ششی تھرور نے بھی ان نتائج کی ستائش کی اور خیر مقدم کیا ہے لیکن تروانت پورم کا نتیجہ تشویش ناک بھی ہے۔تروانت پورم کارپوریشن میں بی جے پی کا کامیاب ہوئی ہے جو کہ چونکانے والی بات ہے۔واضح رہے کہ تروانت پورم کارپوریشن میں ایل ڈی ایف یعنی بائیں بازو کے محاذ کو 45 برسوں سے اکثریت حاصل تھی۔ اب وہاں بی جے پی کی کامیابی جہاں وزیر اعلیٰ پنرئی وجین کی شکست ہے وہیں ششی تھرور بھی اس کے لیے کسی حد تک ذمہ دار ہیں۔ان کی زبانی بی جے پی اور نریندر مودی کی ستائش نے ممکن ہے کہ کچھ کانگریسی ووٹرز کو بی جے پی کی طرف مائل کیا ہو۔ممکن ہے وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ آج نہیں تو کل ششی تھرور پالا بدل سکتے ہیں لہٰذا بی جے پی کی طرف مڑ جانا چاہیے۔ لیکن صرف یہی ایک وجہ نہیں ہوسکتی۔حقیقت یہ ہے کہ بی جے پی ایک عرصے سے کیرالہ میں اپنی جڑیں مضبوط کرنے کی کوشش کررہی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تروانت پورم کارپوریشن میں 101 وارڈوں میں این ڈی اے کو 50، ایل ڈی ایف کو 29 اور یو ڈی ایف کو 19 میں کامیابی مل گئی۔ کیرالہ میں ایل ڈی ایف کی شکست کے کئی اسباب رہے ہیں۔ جب سبری مالا مندر سے سونے کے زیورات کی چوری کا معاملہ سامنے آیا تو بائیں بازو کے کئی لیڈروں کے ملوث ہونے کا الزام عائد کیا گیا اور ایک سینئر پارٹی لیڈر کو گرفتار بھی کیا گیا۔ بی جے پی نے اس ایشو کو خوب اچھالا جس کی وجہ سے ہندو ووٹ اس کی جانب مائل ہوگیا۔ حالانکہ وہی ہندو ووٹ ایک عرصے سے بائیں بازو کو اقتدار میں لاتا رہا ہے۔لیکن بایاں محاذ اس معاملے کو سنبھال نہیں سکا۔ادھر سی پی آئی ایم نے کانگریس پر الزام لگایا کہ وہ جماعت اسلامی کے لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے لیکن کانگریس نے اس کا تر کی بہ تر کی جواب دیا اور انکشاف کیا کہ وہ خود جماعت کے لوگوں کے ساتھ ہے اور جماعت نے 2019 میں سی پی آئی ایم کو ووٹ دیا تھا۔اس طرح یہ الزام خود اس کے گلے پڑ گیا۔

مسلم علاقوں میں بائیں بازو کو سخت نقصان ہوا۔اس کی وجہ یہ رہی کہ عوام میں یہ تاثر پیدا ہوا جو کسی حد تک درست ہے کہ بایاں محاذ ہندوتو طاقتوں کے خلاف لڑائی لڑنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔مرکز کی ایک اسکیم ہے ''پی ایم شری''۔ بایاں بازو پہلے اس کی مخالفت کرتا رہا لیکن پھر اس نے اس کو منظوری دے دی۔جس سے سنگھ پریوار کے خلاف بائیں بازو کی لڑائی کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوگئے۔اس کے علاوہ جب کٹر ہندو رہنماوؤں نے مسلم اکثریتی علاقوں میں مسلمانوں کے خلاف اپنی جارحانہ مہم تیز کی تو وزیر اعلیٰ وجین اور ان کی پارٹی نے خاموشی اختیار کرلی۔انہوں نے مسلمانوں اور اقلیتوں کے حق میں کوئی آواز نہیں اٹھائی جس سے مسلمانوں میں یہ پیغام گیا کہ وہ ان کے ہمدرد نہیں ہیں اور انہوں نے ہندوتو کی طاقتوں کو چھوٹ دے رکھی ہے۔ وجین حکومت گزشتہ سال سے چل رہی ہے جس کی وجہ سے اس کے خلاف عوام میں جذبات پائے جاتے ہیں۔ اس نے بھی بائیں بازو کی شکست کی راہیں کھول دیں۔

ان انتخابات میں ایک اہم بات اور دیکھی گئی جو سوشل میڈیا سے متعلق تھی۔متعدد امیدواروں اور خاص طور پر نوجوان امیدواروں نے اپنی انتخابی مہم میں سوشل میڈیا کا سہارا لیا۔انھوں نے اس کی بنیاد پر اپنی مہم چلائی اور اس کے بہت مثبت نتائج برآمد ہوئے۔مبصرین کا خیال ہے کہ 80 فیصد ایسے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں جنھوں نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا۔واضح رہے کہ اس وقت سوشل میڈیا ایک بہت اہم پلیٹ فارم ثابت ہورہا ہے۔صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس کے اثرات بڑھ رہے ہیں۔حالیہ دنوں میں نیویارک کے میئر کے انتخابات میں ظہران ممدانی کی جیت میں بھی سوشل میڈیا کا بڑا عمل دخل تھا۔سیکڑوں افراد نے سوشل میڈیا پر دن رات مہم چلائی تھی جس کے نتیجے میں ممدانی کی شاندار کامیابی ہوئی۔ ہندوستان میں بھی ایسے ہزاروں انفلوینسر ہیں جو سوشل میڈیا کے ہیرو ہیں۔ عوام اور بالخصوص نوجوان نسل ان کی باتیں سنتی ہے اور ان کی اپیلوں پر کان دھرتی ہے۔خود بی جے پی نے اسی پلیٹ فارم کا سہارا لے کر سیاسی کامیابی حاصل کی ہے۔

بہرحال کیرالہ کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج نے سب کو چونکا دیا ہے۔ جہاں بائیں بازوں کا قلعہ ہل گیا ہے وہیں بی جے پی نے ریاست میں اپنی جڑیں مضبوط کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ کانگریس کو اس کامیابی سے بہت زیادہ خوش ہونے کے بجائے اسے اگلے سال ہونے والے اسمبلی انتخابات میں بہترین حکمت عملی اختیار کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔جس طرح ان مقامی انتخابات میں اس نے شاندار حکمت عملی بنائی اسی طرح اسمبلی انتخابات میں بھی بنانے کی ضرورت ہے۔اگر وہ اس میں کامیاب ہوگئی تو اسمبلی انتخابات میں اسے کامیابی مل سکتی ہے۔

☆☆☆

بہار انتخابات کے غیر فطری نتائج

ووٹر فہرست، نقد اسکیموں اور کارپوریٹ اثرات کے خطرناک مضمرات

آوازِتسنیم

بہار کے حالیہ اسمبلی انتخابات کے نتائج نے ملک کی سیاسی فضا میں ایک غیر معمولی بحث کو جنم دیا ہے۔ عام توقعات اور تقریباً تمام ایگزٹ پولز کے اندازوں کے برعکس سامنے آنے والے اس نتیجے نے سیاسی تجزیہ کاروں، حقوقِ رائے دہی کے ماہرین اور جمہوری عمل پر نظر رکھنے والوں کو حیرت اور تشویش میں مبتلا کردیا ہے۔ یہ نتیجہ انتخابی عمل کے بنیادی ڈھانچے میں ایسی تبدیلیوں کی نشاندہی کرتا ہے جن کے اثرات آنے والے برسوں تک محسوس کیے جائیں گے۔

یہ صورتحال ایک حد تک 2010 کے یادگار انتخابی نتائج کی یاد دلاتی ہے جب اُس وقت کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے اتحاد نے اسمبلی میں 206 نشستیں حاصل کرلی تھیں اور آر جے ڈی محض 22 نشستوں تک محدود ہوگئی تھی۔ مگر وہ ایک بالکل مختلف سیاسی ماحول کا دور تھا—اس وقت نہ مودی عہد کا عروج تھا اور نہ مرکز اور ریاست میں اس قدر یک طرفہ طاقت کا توازن۔ دوسری طرف 2020 کے انتخابات میں حکومت معمولی فرق سے بچی تھی اور 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں بی جے پی کو اپنا عددی اکثریتی مقام کھونا پڑا تھا۔ایسے حالات میں 2025 کے بہار انتخابات کا نتیجہ فطری سیاسی رخ کے خلاف جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جو غیر معمولی عوامل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

انتخابی منظرنامے کو سمجھنے کے لیے دو بڑے حکومتی اقدامات خصوصی توجہ چاہتے ہیں۔ پہلا، ووٹرلسٹ کی خصوصی گہری نظرثانی یعنی ایس آئی آر مہم۔اس کے نتیجے میں تقریباً 69 لاکھ نام حذف کیے گئے جبکہ 25 لاکھ سے زائد نئے نام شامل کیے گئے۔ حیران کن طور پر ایس آئی آر کے مکمل ہونے اور انتخابی اعلان کے بعد بھی تین لاکھ سے زیادہ ووٹروں کا اضافہ ہوا، جس نے انتخابی توازن کو مزید بدل ڈالا۔ بیشتر حلقوں میں ہونے والی یہ تبدیلیاں 2020 میں اپوزیشن کی برتری سے کہیں زیادہ تھیں اور ان کا اثر محدود حلقوں تک نہیں بلکہ وسیع پیمانے پر محسوس کیا گیا۔

ووٹر فہرست میں تبدیلیوں نے صرف رائے دہی پر اثر نہیں ڈالا بلکہ شہری حقوق، فوائد اور شناخت کے حوالے سے خوف اور بے یقینی کو بھی بڑھایا۔ اس بار بہار نے اپنی تاریخ کا سب سے زیادہ ووٹنگ فیصد ریکارڈ کیا، جس میں باہر رہنے والے مخصوص حمایتی ووٹروں کی منظم منتقلی اور خصوصی ٹرینوں کی فراہمی جیسے اقدامات نے اہم کردار ادا کیا۔ انتظامیہ کی جانب سے کھلے جانبدارانہ رویے اور منظم انداز میں ہونے والی حکومت نواز ووٹنگ کی اجازت نے انتخابی شفافیت پر مزید سوالات اٹھادیے۔

دوسرا اہم پہلو انتخابی مہم کے دوران اور اس سے پہلے بڑی سطح پر نقد اسکیموں اور براہِ راست مالی مراعات کا اعلان اور تقسیم ہے۔ بڑھتے عوامی غصے کو کم کرنے کیلئے تین بڑے اقدامات سامنے لائے گئے: بزرگ اور معذوری پنشن کو 400 سے بڑھا کر 1100 روپے ماہانہ کرنا، 125 یونٹ تک بجلی مفت فراہم کرنا اور سب سے نمایاں 1.5 کروڑ خواتین کو 10 ہزار روپے کی یک مشت ادائیگی۔ یہ اقدام صرف انتخابی فائدے کے لیے تھا یا سماجی بہبود کے لیے یہ سوال اب بھی معلق ہے، مگر اس کے سیاسی اثرات نمایاں ہیں۔

نام نہاد 'کھیہ منتری مہیلا روزگار اسکیم' کا آغاز بھی انتخابی شیڈول سے کچھ روز قبل ہوا اور اس کے تحت رقوم کی تقسیم انتخابی مدت کے دوران بھی جاری رہی۔ مرکزی وزیر داخلہ نے اسے قرض کے طور پر دی گئی رقم قرار دیا مگر خواتین میں بڑھتے مائیکرو فنانس جبر کے سبب نتیش کمار نے وضاحت کی کہ یہ قرض نہیں بلکہ بلاواپسی رقم ہے۔ اس کے ساتھ ہی 1,80,000 'جیویکا رضا کاروں' کو انتخابی عملے میں شامل کرنے کا انکشاف مزید سوالات پیدا کرتا ہے۔

اسی تناظر میں ایک اور معاملہ 'پیر پینتی اڈانی بجلی معاہدہ' میڈیا کی نظروں سے اوجھل رہا۔ اس معاہدے کے تحت محض ایک روپیہ سالانہ لیز پر 1050 ایکڑ زمین اور مہنگے نرخوں پر بجلی خرید کی ضمانت دی گئی۔ سابق مرکزی وزیر توانائی آر کے سنگھ نے اسے 620 ارب روپے کا گھوٹالہ قرار دے کر سی بی آئی تحقیقات کا مطالبہ کیا، جس کے فوراً بعد وہ پارٹی سے نکال دیے گئے۔ اس واقعہ نے کارپوریٹ مفادات، انتخابی سرمایہ کاری اور سیاسی مراعات کے باہمی رشتے پر سنگین سوالات کھڑے کیے۔

اسی پس منظر میں کارپوریٹ سرپرستی میں چلنے والی انتخابی مہم اور تشہیر کے ماڈل کو بھی نظرانداز نہیں کیا جاسکتا۔ انتخابی ماحول میں غیر معمولی تشہیری سرگرمی، سرمایہ کے بے تحاشہ استعمال اور میڈیا بیانیے پر اثراندازی نے انتخابی منصفانہ توازن کو متاثر کیا ہے۔

ایک اور تشویشناک پہلو مسلم نمائندگی میں تاریخی کمی ہے۔ اس بار اسمبلی میں مسلمانوں کی تعداد 19 سے گھٹ کر صرف 11 رہ گئی ہے، جب کہ بی جے پی کے 101 امیدواروں کی فہرست میں ایک بھی مسلمان شامل نہیں تھا۔اس کے برخلاف 10.7 فیصد اعلیٰ ذات آبادی سے 49 امیدوار فراہم کیے گئے۔ ساتھ ہی این ڈی اے کے کیمپ میں عام/اعلیٰ ذات کے 69 ارکان دیہی پس منظر رکھنے والے او بی سی ارکان سے زیادہ ہیں، جو سماجی توازن کے رجحان کو تبدیل کرتا ہے۔

سی پی آئی (ایم ایل) نے بیس نشستوں پر الیکشن لڑا مگر صرف دو میں کامیابی حاصل کرسکی، اگرچہ کئی نشستوں پر معمولی مارجن سے شکست ہوئی۔ اتحاد کیلئے ضروری ہے کہ نتائج کا سنجیدہ جائزہ لیا جائے، خامیوں کی نشاندہی کی جائے اور مستقبل کے لیے مؤثر حکمتِ عملیاں تشکیل دی جائیں۔

نتیش کمار کی نئی حکومت میں بی جے پی کا اثر پہلے سے کہیں زیادہ گہرا ہوگا اور آر ایس ایس کے نظریاتی ڈھانچے کے مطابق بہار کو 'بلڈوزر تجربہ گاہ' بنانے کی پالیسی کا خطرہ بھی بڑھ رہا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ غیر معمولی اکثریت رکھنے والی حکومتیں اکثر جلد بکھر جاتی ہیں مگر اس بار صورتحال الگ ہے کیونکہ اس کے اثرات بہار سے آگے بڑھ کر آنے والے انتخابات جیسے آسام، مغربی بنگال، تمل ناڈو، کیرالہ اور پھر اتر پردیش تک پہنچنے کا امکان ہے۔

یہ نتائج جمہوریت، نمائندگی، انتخابی شفافیت اور ریاستی طاقت کے استعمال کے بارے میں بنیادی سوالات اٹھاتے ہیں۔ بہار کا یہ انتخاب محض ایک سیاسی موڑ نہیں بلکہ جمہوری ڈھانچے کے مستقبل کا سنجیدہ امتحان ہے۔

☆☆☆

ہم ستیہ اور اہنسا کے ذریعہ مودی حکومت کو ہٹا کر رہیں گے

- **راہول گاندھی نے نام لے کر چیف الیکشن کمشنر کو نشانہ تنقید بنایا**
- **نئی دہلی کے رام لیلا میدان میں 'ووٹ چور، گدی چھوڑ' ریالی سے کانگریس قائد کا خطاب**

آوازِتسنیم

کانگریس قائد راہول گاندھی نے اتوار کے دن کہا کہ ان کی پارٹی ''ستیہ'' (سچائی) کے ساتھ کھڑی ہے۔انہوں نے نریندر مودی۔آر ایس ایس حکومت کو ہٹا دینے کا عہد کیا۔نئی دہلی کے رام لیلا میدان میں اپنی پارٹی کی ''ووٹ چور، گدی چھوڑ'' ریالی سے خطاب میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔انہوں نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار اور الیکشن کمشنرس سکھبیر سنگھ سندھو اور وویک جوشی کا نام لیتے ہوئے الزام عائد کیا کہ یہ لوگ بی جے پی کے لئے کام کررہے ہیں۔ قائد اپوزیشن لوک سبھا نے کہا کہ ہم ستیہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور نریندر مودی۔آر ایس ایس حکومت کو اقتدار سے بے دخل کردیں گے۔ ان لوگوں کے پاس ستہ (اقتدار) ہے اور یہ لوگ ووٹ چوری کررہے ہیں۔ راہول گاندھی نے دعویٰ کیا کہ الیکشن کے دوران بی جے پی نے 10 ہزار روپے لوگوں کے کھاتوں میں منتقل کئے لیکن الیکشن کمیشن نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ستیہ اور استیہ کی اِس لڑائی میں الیکشن کمیشن بی جے پی حکومت کیلئے کام کررہا ہے۔مودی نے الیکشن کمیشن کو امیونٹی دینے کیلئے نیا قانون بنایا۔ہم اس قانون کو بدل دیں گے اور الیکشن کمشنرس کے خلاف کارروائی کریں گے۔انہوں نے زور دے کر کہا کہ وقت لگے گا لیکن سچائی کی جیت ہوکر رہے گی۔ ہم سچائی اور عدم تشدد کے ساتھ کام کریں گے اور مودی اور شاہ کو ہرائیں گے۔کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے اپنے خطاب میں کہا کہ ووٹ چوری کرنے والے غدار ہیں۔انہیں اقتدار سے ہٹا دینے کی ضرورت ہے تاکہ حق رائے دہی اور دستور کو بچایا جائے۔انہوں نے کہا کہ تمام ہندوستانیوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ کانگریس کی آئیڈیالوجی کو متحدہ طور پر مستحکم کریں کیونکہ کانگریس واحد پارٹی ہے جو ملک کو بچاسکتی ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ملک کو ختم کردے گی۔ کھرگے نے کہا کہ بی جے پی والے غدار اور ڈرامے باز ہیں۔انہیں اقتدار سے ہٹا دینے کی ضرورت ہے۔ کانگریس صدر نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے بیٹے کے آپریشن کیلئے بنگلور نہیں گئے اور ریالی کیلئے دہلی میں موجود رہے کیونکہ ان کے خیال میں 140 کروڑ عوام کو بچانا اہم ہے۔آئی اے این ایس کے بموجب قائد اپوزیشن لوک سبھا راہول گاندھی نے آج ریالی سے خطاب میں بی جے پی کی انتخابی دھاندلیوں اور الیکشن کمیشن سے اس کے سازباز کا الزام دہرایا۔انہوں نے کہا کہ بی جے پی ووٹ چوری کرتی ہے۔ راہول گاندھی نے کہا کہ ہندو مذہب اور دیگر تمام مذاہب میں سچ کو سب سے بالاتر مانا گیا ہے۔ ہم اِس حکومت کو اقتدار سے ہٹا کر رہیں گے۔ پارٹی صدر کھرگے نے کہا کہ بی جے پی اور آر ایس ایس اپنی تفرقہ پسند آئیڈیالوجی کے ذریعہ زہر کے بیج بو رہی ہیں۔انہوں نے الزام عائد کیا کہ بی جے پی قائدین ڈرامے کرتے ہیں۔لوگوں کو بی جے پی سے پوری قوت سے لڑنا ہوگا۔انہوں نے کہا کہ بی جے پی غریب عوام کا حق رائے دہی چھیننا چاہتی ہے۔انہوں نے کہا کہ بی جے پی ہمیشہ الزام عائد کرتی ہے کہ راہول گاندھی پارلیمنٹ اجلاس کے بعد بیرون ملک چلے جاتے ہیں لیکن وزیر اعظم مودی خود بیرونی دورے ایسے وقت کرچکے ہیں جب پارلیمنٹ اجلاس جاری تھا۔ کھرگے نے کہا کہ بی جے پی اور آر ایس ایس نے جدوجہد آزادی میں کبھی بھی حصہ نہیں لیا لیکن اب یہ لوگ وندے ماترم پر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔

تینوں الیکشن کمشنرس کو جواب دینا ہوگا: پرینکا

کانگریس قائد پرینکا گاندھی وڈرا نے اتوار کے دن کہا کہ انتخابی عمل کا ہر قدم شبہات پیدا کرتا ہے۔انہوں نے زور دے کر کہا کہ چیف الیکشن کمشنر اور ان کے دو نائبین کو جواب دینا ہوگا کہ انہوں نے عوام کا حق رائے دہی چھیننے کی ''سازش'' کیسے کی۔ رام لیلا میدان میں کانگریس کی میگا ریالی سے خطاب میں پرینکا گاندھی نے کہا کہ ایسے وقت جبکہ ملک کے ادارے روندے جارہے ہیں ہندوستانیوں کو اٹھ کھڑا ہونا ہوگا۔انہوں نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار اور الیکشن کمشنرس سکھبیر سنگھ سندھو اور وویک جوشی کا نام لے کر کہا کہ بی جے پی انہیں بچا نہیں سکے گی کیونکہ یہ لوگ ایک نہ ایک دن جواب دینے پر مجبور ہوجائیں گے کہ عوام کا حق رائے دہی چھیننے کی سازش کیوں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کو میری للکار ہے کہ وہ بیالٹ پیپر پر الیکشن لڑ کر دکھائے۔اسے پتہ ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں جیتے گی۔ پرینکا نے حاضرین جلسہ سے کہا کہ بہار کی ہار سے مایوس نہ ہوں کیونکہ سارا ملک جانتا ہے کہ بی جے پی، ووٹ چوری سے جیتتی ہے۔

مرکز نے اداروں کو کھوکھلا کردیا: سچن پائلٹ

کانگریس قائد سچن پائلٹ نے الزام عائد کیا کہ مودی حکومت، اداروں کو کھوکھلا کررہی ہے۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ یقینی بنائیں کہ الیکشن کمیشن غیر جانبداری سے کام کرے اور ہندوستانی جمہوریت ممتاز رہے۔ رام لیلا میدان میں ووٹ چور، گدی چھوڑ ریالی سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری پر سوال اٹھ رہے ہیں لیکن کوئی جواب نہیں مل رہا ہے۔ راجستھان کے سابق ڈپٹی چیف منسٹر نے کہا کہ یہاں لوگ اس حکومت کو للکارنے کیلئے اکھٹا ہوئے ہیں جس نے گزشتہ 11 برس میں اداروں کو کھوکھلا کرنے کا ماحول تیار کیا۔ اسے چلنے نہیں دیا جاسکتا۔ پارٹی جنرل سکریٹری نے کہا کہ ہمارے پڑوسیوں چین، پاکستان، سری لنکا اور نیپال کو جمہوریت کی مثال نہیں سمجھا جاتا لیکن ہندوستان کو اس کے الیکشن سسٹم کے جانبداری سے بالاتر ہونے کی وجہ سے ایسا سمجھا جاتا ہے۔ہمیں سڑکوں پر احتجاج جاری رکھنا ہوگا۔عوام کا فرض بنتا ہے کہ وہ یہ یقینی بنائیں کہ الیکشن اسٹرکچر غیر جانبدار رہے۔

☆☆☆

سڈنی میں یہودی اجتماع کے قریب فائرنگ، 10 ہلاک

آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں مقامی وقت کے مطابق اتوار کی شام بونڈی بیچ پر ایک یہودی اجتماع کے قریب فائرنگ کے واقعہ میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہوگئے۔مہلوکین میں ایک بندوق بردار شامل ہیں۔ 12 دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں۔ مقامی میڈیا نے پولیس کے حوالہ سے یہ اطلاع دی۔ دوسرا شوٹر زخمیوں میں شامل ہے اور اسے حراست میں لے لیا گیا۔اے بی سی نیوز نے یہ اطلاع دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لوگوں کو ابھی بھی بونڈی بیچ سے دور رہنا چاہئے۔علاقہ میں بم کا خطرہ ابھی بھی برقرار ہے۔ وہاں ایک دھماکو آلہ کو ناکارہ کیا جارہا ہے۔آسٹریلیائی وزیر اعظم انتھونی البانیز نے بونڈی کے مناظر کو تکلیف دہ قرار دیا۔انہوں نے کہا کہ آسٹریلیائی فیڈرل پولیس کمشنر اور نیوساؤتھ ویلز کے وزیر اعظم سے ان کی بات ہوئی ہے۔ایکس پر بیان میں انہوں نے کہا کہ وہاں کے مناظر تکلیف دہ ہیں۔ پولیس اور ایمرجنسی ورکرس جانیں بچانے کے لئے وہاں پہنچ گئے ہیں۔ہم نیوساؤتھ ویلز پولیس کے ساتھ مل کر کام کررہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ انہیں اس حملہ سے تکلیف پہنچی۔انہوں نے اسے آسٹریلیا کی سڑکوں پر گزشتہ دو سال سے جاری یہودی مخالف مہم کا نتیجہ قرار دیا۔آسٹریلین جیوش اسوسی ایشنس کے سی ای او رابرڈ گریوری نے کہا کہ البانیز حکومت کو کئی بار خبردار کیا گیا تھا لیکن وہ یہودی فرقہ کے تحفظ کیلئے مناسب کارروائی کرنے میں ناکام رہی۔

انگلینڈ کے سابق کرکٹر وان، بونڈی بیچ واقعہ بچ گئے

انگلینڈ کے سابق کرکٹر مائیکل وان آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے بونڈی بیچ پر واقع ریسٹورنٹ میں پھنس گئے۔ بونڈی بیچ پر دو مسلح افراد نے اجتماعی فائرنگ کی۔ گولیوں کی کئی راؤنڈز نے ساحل سمندر پر موجود لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ سڈنی مارننگ پوسٹ کے مطابق فائرنگ کے نتیجے میں شوٹر سمیت 12 افراد ہلاک ہوئے۔ سینکڑوں لوگ بونڈی بیچ پر یہودیوں کا تہوار ہنوکا منانے کیلئے جمع تھے جب حملہ آوروں نے فائرنگ کی۔ انگلینڈ کے سابق کرکٹر وان نے ٹوئٹر پر شیئر کیا کہ وہ بھی بونڈی بیچ کے ایک ریسٹورنٹ میں پھنس گئے تھے لیکن اب بحفاظت گھر واپس آگئے ہیں۔ وان نے انسٹاگرام پر لکھا کہ بونڈی کے ایک ریستوران میں پھنس جانا بہت خوفناک تھا۔ اب میں صحیح سلامت گھر پہنچ گیا ہوں۔لیکن ہنگامی خدمات اور دہشت گرد کا مقابلہ کرنے والے شخص کا بہت شکریہ۔ تمام متاثرہ افراد کیلئے میری تعزیت۔ اتوار کو نیوساؤتھ ویلز پولیس کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دو افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ اس دوران فائرنگ کی ایک ویڈیو بھی منظر عام پر آئی ہے۔وائرل ویڈیو میں ایک مقامی شخص نے فائرنگ کرنے والوں میں سے ایک کو پکڑ لیا۔ شوٹنگ کے دوران یہ شخص ایک کار کے پیچھے چھپا ہوا نظر آتا ہے۔شوٹر کو پارکنگ میں بندوق سے فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا جارہا ہے۔ جیسے ہی شوٹر گھومتا ہے، کار کے پیچھے چھپا ہوا آدمی اسے پیچھے سے ٹیک لگاتا ہے۔ ایک ہاتھا پائی ہوتی ہے جس کے دوران آدمی حملہ آور سے بندوق چھیننے میں کامیاب ہوجاتا ہے۔ واضح رہے کہ انگلینڈ کی ٹیم اس وقت ایشز سیریز کیلئے آسٹریلیا کے دورے پر ہے۔

तोगड़िया बोले- राजनीति का असली उद्देश्य सेवा से जुड़ा होना

सनातन के नाम पर जिम्मेदारी लेने वालों को धरातल पर सेवा करनी होगी

आवाज़ ए तसनीम

जयपुर। अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद के अध्यक्ष डॉ. प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि राजनीति का असली उद्देश्य सेवा से जुड़ा होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की पहचान यही है कि एक हिंदू, दूसरे हिंदू की बिना स्वार्थ मदद करे। उन्होंने बताया कि समाज पदवी या उपाधियों से नहीं, बल्कि लगातार सेवा, संगठन और सकारात्मक सोच से मजबूत होता है।

जयपुर में संगठन से जुड़े लोगों से मुलाकात के दौरान विहिप अध्यक्ष तोगड़िया ये बोल रहे थे।

डॉ. तोगड़िया ने कहा कि सनातन की ताकत जमीन पर किए गए काम से बनती है। उन्होंने यह भी बताया कि आज हर गली-मोहल्ले में अगर कोई व्यक्ति हिंदुत्व के लिए खड़ा दिखता है, तो इसे नकारात्मक नजर से नहीं देखना चाहिए।

उन्होंने राजस्थान का उदाहरण देते हुए बताया कि जैसे पहले पानी की भारी कमी थी और अब घर-घर पानी पहुंच रहा है, उसी तरह अगर हर मोहल्ले में समाज के लिए काम करने वाला व्यक्ति सक्रिय है तो यह सामाजिक मजबूती का संकेत है।

हर गांव-मोहल्ले में हो हनुमान चालीसा का पाठ

उन्होंने कहा कि केवल बड़ी-बड़ी उपाधियां लेना काफी नहीं है। सनातन और हिंदू धर्म के नाम पर जिम्मेदारी लेने वालों को धरातल पर सेवा करनी होगी। इसी क्रम में उन्होंने यह संकल्प भी साझा किया कि हर गांव और हर मोहल्ले में शनिवार या मंगलवार की शाम सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए। उन्होंने परिवार और समाज से जुड़े 30 सूत्रों की भी जानकारी दी, जिनके पालन से परिवार रोग और चिंता से मुक्त रह सकता है और जीवन में सुरक्षा, आरोग्य और स्थिरता आती है।

डॉ. तोगड़िया ने बताया कि हमारा लक्ष्य ऐसा संगठित हिंदू समाज खड़ा करना है, जो संख्या से नहीं बल्कि संगठन और संकल्प से मजबूत हो। उन्होंने कहा कि भारत में एक अनुशासित और मजबूत सामाजिक संगठन खड़ा करना ही अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद और ओजस्विनी जैसे संगठनों का उद्देश्य है।

राजस्थान सरकार के दो साल पूरे होने पर दी बधाई

धर्मांतरण के मुद्दे पर उन्होंने बताया कि सेवा सबसे प्रभावी रास्ता है। राजस्थान में लागू धर्मांतरण कानून को उन्होंने सकारात्मक कदम बताया और कहा कि इससे जबरन या प्रलोभन से होने वाले धर्मांतरण पर रोक लगेगी।

साथ ही, राजस्थान सरकार के दो साल पूरे होने पर उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बधाई दी और बताया कि समाज को जोड़ने वाला सेवा कार्य ही सनातन की असली शक्ति है।

श्रमणाचार्य विनिश्चय सागर का 28वां दीक्षा महोत्सव संपन्न

बाड़ा पदमपुरा में हुआ आयोजन, महाराज बोले- गुरु कृपा से शिष्य की पहचान

आवाज़ ए तसनीम

चाकसू। चाकसू उपखंड मुख्यालय के बाड़ा पदमपुरा में रविवार शाम 5 बजे श्रमणाचार्य विनिश्चय सागर महाराज का 28वां संयम दीक्षा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया।

विनोद जैन कोटखावदा ने बताया कि इस आयोजन में जयपुर सहित देशभर से श्रद्धालु शामिल हुए। महोत्सव के दौरान विनिश्चय सागर महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि गुरु कृपा से ही शिष्य की पहचान होती है। गुरु के उपकार को जन्मों-जन्मों तक नहीं भुलाया जा सकता।

महाराज ने आगे कहा कि जब वास्तविकता सामने आती है, तो सारे विकल्प स्वतः समाप्त हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि 27 वर्ष पूर्व गुरु विराग सागर महाराज द्वारा दी गई मुनि दीक्षा का उपकार आज फलीभूत हो रहा है। उन्होंने सभी से वैराग्य और दीक्षा के भाव बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि आज बनाए गए भाव एक दिन अवश्य वैराग्य की ओर ले जाएंगे। जैन दर्शन के अनुसार, संन्यास और दीक्षा परिग्रह के त्याग के बिना संभव नहीं है। भगवान पदमप्रभु के दर्शन से भावों में निर्मलता आती है।

महोत्सव से पूर्व चित्र अनावरण, दीप प्रज्जवलन, पाद पक्षालन, संगीतमय पूजा, शास्त्र भेंट, जाप्य माला भेंट, नव वर्ष कैलेंडर विमोचन और मंगल प्रवचन जैसे कई आयोजन किए गए।

प्रातः 11:30 बजे आचार्य विनिश्चय सागर महाराज ससंघ को बैंड-बाजों के साथ संत भवन से मंदिर के दर्शन कराते हुए झांझरी सभागार तक लाया गया। दोपहर 12:15 बजे समाज श्रेष्ठी धर्मचंद राकेश और लोकेश लुहाड़िया (आकोदा वाले) ने ध्वजारोहण कर 28वें दीक्षा दिवस समारोह का शुभारंभ किया।

महोत्सव के दौरान दिव्या बाकलीवाल, तन्वी जैन, आयुषी वैशाली और पायल टीम ने नृत्य प्रस्तुत किया। मंगलाचरण के बाद समाज श्रेष्ठी अशोक-शकुंतला और अंकित-प्रियंका चांदवाड़ ने स्वर्ण कलश से, जबकि मयंक-विजया सावला ने रजत कलश से वाक्केशरी श्रमणाचार्य विनिश्चय सागर महाराज का पाद पक्षालन किया। सुरेंद्र-सुनीता हल्देनिया, अनिल पुलकित लुहाड़िया और आशीष जैन परिवार ने आचार्य श्री को मुख्य शास्त्र भेंट किया। इसके अतिरिक्त, समाज श्रेष्ठी अशोक-प्रेमलता बाकलीवाल, पुष्पा, कुलदीप सोनी, कुसुम अभिषेक साखूनिया, मनीष-संतोष बगड़ा, प्रदीप-सुंदर काला, डॉ. अजीत जैन और शांति जैन द्वारा जैन समाज की परंपरा के अनुसार सभी मुनिराजों को भेंट अर्पित की गई।

रियाज अहमद और विभा चौधरी ने रच दिया इतिहासः जीते तिहरे खिताब, रघु सिन्हा आईटीएफ मास्टर्स-400 टेनिस प्रतियोगिता का जयपुर में हुआ समापन

आवाज़ ए तसनीम

जयपुर। रघु सिन्हा आईटीएफ मास्टर्स 400 टेनिस प्रतियोगिता का समापन जयपुर क्लब के क्ले कोर्ट्स पर रोमांचक फाइनल मुकाबलों के साथ भव्य रूप में हुआ। टूर्नामेंट के अंतिम दिन जयपुर के रियाज अहमद और दिल्ली की विभा चौधरी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन-तीन खिताब अपने नाम कर प्रतियोगिता के सबसे सफल खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया।

पुरुष 40+ एकल वर्ग के फाइनल में रियाज अहमद ने कड़े मुकाबले में पुनर भसीन को 6-4, 7-5 से पराजित कर खिताब जीता। इसके बाद पुरुष युगल में रियाज ने स्वर्णदीप सिंह डोडी के साथ मिलकर पुनर भसीन और रोहन भसीन की जोड़ी को तीन सेटों के संघर्षपूर्ण मुकाबले में 4-6, 6-2, 10-8 से हराया। मिक्स्ड डबल्स में भी रियाज अहमद ने रानी स्मिता जैन के साथ एलिस जॉय और स्वर्णदीप सिंह डोडी की जोड़ी को 2-6, 6-1, 10-5 से मात देकर अपना तीसरा खिताब पूरा किया।

विभा चौधरी का महिला वर्ग में दबदबा

महिला वर्ग में दिल्ली की विभा चौधरी ने भी बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए तिहरा खिताब जीता। महिला 45+ एकल फाइनल में उन्होंने स्मिता रविंद्र को 6-2, 6-1 से हराया। महिला युगल में रानी स्मिता जैन के साथ मिलकर एलिस जॉय और संजना जैन की जोड़ी को 6-3, 6-0 से पराजित किया। मिक्स्ड डबल्स में नरेंद्र सिंह चौधरी के साथ मिलकर विभा चौधरी ने रुचि शर्मा और जगदीश तनवार को 6-4, 2-6, 10-7 से हराकर तीसरा खिताब अपने नाम किया।

पुरुष एकल में 45+ वर्ग का खिताब नरेंद्र सिंह चौधरी ने, 50+ में जगदीश तनवार, 55+ में गुरदर्शन रमणा, 60+ में पुनीत गुप्ता और 75+ वर्ग में अजीत पेंढारकर ने जीता। महिला एकल 30+ वर्ग में एलिस जॉय विजेता रहीं।पुरुष युगल और महिला युगल वर्गों में भी विभिन्न आयु वर्गों में कड़े और रोमांचक मुकाबले देखने को मिले।

समापन समारोह के मुख्य अतिथि जयपुर क्लब के अध्यक्ष अजीत सक्सेना रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में क्लब सचिव हिमांशु सहगल और प्रो. राजीव शर्मा उपस्थित रहे। खिलाड़ियों ने आयोजन की उत्कृष्ट व्यवस्थाओं, ग्राउंड स्टाफ, बॉल बॉय और चेयर अंपायर्स के व्यवहार की जमकर सराहना की। कई खिलाड़ियों ने इसे देश के सर्वश्रेष्ठ मास्टर्स टेनिस आयोजनों में से एक बताया।

क्लब अध्यक्ष सुरेंद्र गोलछा ने टूर्नामेंट की सफल डिजाइन और व्यवस्थाओं के लिए वरदान सिंह तालेड़ा को सम्मानित किया। रघु सिन्हा माला माथुर ट्रस्ट के ट्रस्टी सुधीर माथुर ने समापन की घोषणा करते हुए सभी अतिथियों और खिलाड़ियों का आभार जताया। टूर्नामेंट डायरेक्टर प्रदीप जैन ने आईटीएफ मैच रेफरी तेजल कुलकर्णी को टूर्नामेंट के अनुशासित और समयबद्ध संचालन के लिए धन्यवाद दिया।

इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में 6 विदेशी खिलाड़ियों सहित देश के 22 राज्यों से खिलाड़ियों ने भाग लिया। खिलाड़ियों ने आईटीएफ कमेटी में टूर्नामेंट को अगले वर्ष आईटीएफ 700 स्तर तक अपग्रेड कराने के लिए सकारात्मक सुझाव देने का भरोसा भी जताया। समापन समारोह का संचालन ललित सिंह तालेड़ा ने किया।

सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी

जयपुर में गलत OMR मिलने पर अभ्यर्थियों का फूटा गुस्सा, स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग

आवाज़ ए तसनीम

जयपुर। जयपुर में सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को गलत ओएमआर शीट थमा दी गई। इतना ही नहीं इस दौरान आपत्ति पर सुधार की जगह व्हाइटनर इस्तेमाल करने का दबाव बनाया गया। जिसके बाद अभ्यर्थियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। ऐसे में स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली।

गुस्साए अभ्यर्थियों ने समय पर समाधान और अतिरिक्त समय न मिलने कारण स्कूल प्रबंधन पर भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। इस दौरान नाराज अभ्यर्थियों ने प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

दरअसल, नेशनल स्टूडेंट सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट की ओर से सीनियर टीचर की भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। देशभर में एकलव्य मॉडल स्कूल में 1460 पदों पर होने वाली सीनियर टीचर भर्ती का स्कूल में सेंटर बनाया गया था।

अभ्यर्थियों को गलत ओएमआर शीट थमाई

जहां रविवार को सुबह 9 से 11:30 तक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाना था। लेकिन भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को गलत ओएमआर शीट दे दी गई। जिसको लेकर जब अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज की, तो स्कूल प्रबंधन ने अभ्यर्थियों को सुधार का वादा किया। लेकिन कुछ देर बाद स्कूल प्रबंधन व्हाइटनर लेकर पहुंच गया। इस दौरान अभ्यर्थियों से ओएमआर शीट में व्हाइटनर का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। जिस पर अभ्यर्थियों ने नाराजगी जाहिर की। इसके बाद एक बार फिर अभ्यर्थियों को उनकी पुरानी ओएमआर शीट दी गई। लेकिन तब तक लगभग डेढ़ घंटे का वक्त बीत चुका था।

स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग

इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्कूल प्रबंधन की ओर से अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय देने का वादा किया गया। लेकिन सुबह 11:30 बजे ही पेपर खत्म कर दिया गया। जिसके बाद 25 नाराज अभ्यर्थियों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूरे मामले को लेकर अभ्यर्थी सरकार से स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

स्कूल प्रबंधन ने परीक्षा में की बड़ी गड़बड़ी

भर्ती परीक्षा देने पहुंचे स्टूडेंट दिनेश ने बताया कि आज स्कूल के टीचर्स द्वारा बड़ी गड़बड़ी की गई। पहले तो हमें गलत ओएमआर शीट दे दी गई। जब हमने इसका विरोध किया, तो सुधार के लिए व्हाइटनर का इस्तेमाल करने को लेकर दबाव बनाया गया। जबकि नियमों के तहत ओएमआर शीट में व्हाइटनर का इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता है।

व्हाइटनर के इस्तेमाल के कारण चेक नहीं होगी OMR शीट

उन्होंने कहा कि नियमों के तहत ऐसा करने पर हमारी ओएमआर शीट चेक ही नहीं होगी। लेकिन बावजूद इसके स्कूल प्रबंधन द्वारा हम पर दबाव बनाया गया। इसके बाद जब हमने इसका विरोध किया। तो उन्होंने फिर से अपनी गलती में सुधार कर हमें अपना पेपर दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की वजह से लगभग 1 घंटे तक हम परेशान होते रहे।

अभ्यर्थियों की सालों की तैयारी पर पानी फिरा

दिनेश ने बताया कि इसके बाद न हमें एक्स्ट्रा टाइम दिया गया न ही स्कूल प्रबंधन की ओर से की गई गलती में सुधार किया गया। जिसकी वजह से अब हमारी सालों की तैयारी पर पानी फिर गया है। ऐसे में हम सरकार से मांग करते हैं कि लापरवाह स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई कर हमें फिर से मौका दिया जाए।

स्कूल प्रबंधन पर भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप

वहीं परीक्षा देने पहुंची सुमित्रा ने कहा कि स्कूल प्रबंधन की ओर से न सिर्फ हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। बल्कि, हमारे साथ बदतमीजी और दुर्व्यवहार भी किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर वहां का स्टाफ ने हमें अपशब्द भी कहे। ऐसे में हम सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह के दोषी लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए।

सुमित्रा ने कहा कि इस मांग को लेकर हम जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों को ज्ञापन भी देंगे। वहीं इस पूरे मामले में हमने स्कूल प्रबंधन से भी उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई है।

जयपुर में बिजनेसमैन का किडनैप, फिरौती मांगी

धारदार हथियार से हमला, कार में कंबल डालकर पीटा, लूटकर भागे

आवाज़ ए तसनीम

जयपुर। जयपुर में कार सवार बदमाशों ने बिजनेसमैन को बंधक बना लिया। आरोपियों ने 5 घंटे तक उसके साथ जमकर मारपीट की। इसके बाद उससे 2 लाख रुपए लूटकर फरार हो गया।

मारपीट के दौरान बदमाशों ने बिजनेसमैन को चाकू मारकर घायल भी कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि उससे 50 लाख की फिरौती भी मांगी गई थी। घटना शनिवार रात करीब 8.30 बजे सांगानेर थाना क्षेत्र की है।

टोंक से जयपुर आया था बिजनेसमैन

बिजनेसमैन विनोद जैन (39) ने बताया कि मैं टोंक (निवाई) का रहने वाला हूं। स्टेशनरी सामान का बिजनेस करता हूं। शनिवार को वह काम के सिलसिले में जयपुर आया था। रात करीब 8:30 बजे वापस टोंक जाने के लिए सांगानेर बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहे थे।

इसी बीच सांगानेर बस स्टैंड पर एक स्विफ्ट कार आकर रुकी। कार में दो-तीन लोग टोंक जाने के लिए बैठ गए। उन्हें देखकर वह भी कार में सवार हो गया।

करीब 8-10 किलोमीटर जाने के बाद कार में पहले से बैठे चारों बदमाशों ने चाकू की नोंक पर उसे धमकाया।

हाथ-पैर बांधकर कंबल डालकर पीटा

विनोद जैन ने बताया कि बदमाशों ने उसके मुंह पर पट्टी बांध दी। बदमाशों ने उसके हाथ-पैर रस्सी से बांध दिए और ऊपर से कंबल डाल दिया।

शोर मचाने पर बदमाश चलती कार में उसके साथ मारपीट करने लगे। बदमाशों ने चाकू दिखाकर उसे जान से मारने की धमकी दी और चुप रहने को कहा।

उसकी जेब से डेबिट कार्ड निकालकर पिन नंबर पूछने लगे। पिन नंबर नहीं बताने पर बदमाशों ने उसकी उंगली पर चाकू मार दिया। पिन नंबर पूछकर बदमाशों ने तीन अलग-अलग जगहों से डेबिट कार्ड के जरिए 2 लाख रुपए लूट लिए।

चलती कार से फेंककर भागे

कार सवार बदमाशों ने चाकू की नोंक पर उसे और उसके घरवालों को 50 लाख रुपए देने के लिए धमकाया। बदमाश करीब 5 घंटे तक उसे कार में घुमाते रहे और टॉर्चर करते रहे। पीड़ित बिजनेसमैन के रोने-गिड़गिड़ाने पर बदमाश उसे रात करीब 1:30 बजे बीलवा के पास चलती कार से फेंक कर फरार हो गए।

Munambam Land Dispute में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री, Waqf प्रॉपर्टी मामले में HC के आदेश पर रोक

आवाज़ ए तसनीम

केरल के मुनंबम इलाके की जमीन को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है. देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था ने केरल हाईकोर्ट की उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसमें मुनंबम की जमीन को वक्फ संपत्ति न मानने की बात कही गई थी. अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक जमीन की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा और यथास्थिति (Status Quo) बनाए रखी जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने केरल वक्फ संरक्षण वेदी की विशेष अनुमति याचिका पर दिया है. कोर्ट ने केरल सरकार को नोटिस जारी करते हुए छह हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी 2026 को होगी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि केरल सरकार के जरिये गठित जस्टिस सी.एन. रामचंद्रन नायर जांच आयोग के कामकाज पर कोई रोक नहीं लगाई गई है और आयोग अपनी जांच जारी रख सकता है. पीठ ने अपने आदेश में कहा कि अगली सुनवाई तक केरल हाईकोर्ट की उस घोषणा पर रोक रहेगी, जिसमें विवादित जमीन को वक्फ संपत्ति नहीं बताया गया था. साथ ही अदालत ने यह निर्देश दिया कि जमीन से जुड़ी मौजूदा स्थिति में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाए. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच आयोग के काम में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया गया है.

सिद्दीक सैत ने जमीन की थी दान

यह विवाद केरल के एर्नाकुलम जिले के मुनंबम क्षेत्र की करीब 135 एकड़ जमीन से जुड़ा है. यह जमीन साल 1950 में सिद्दीक सैत नाम के शख्स के जरिये फारूक कॉलेज को दान में दी गई थी. उस समय इस जमीन पर कई स्थानीय परिवार पहले से ही रह रहे थे. बाद के सालों में कॉलेज ने इस जमीन के कुछ हिस्से इन्हीं निवासियों को बेच दिए थे.

इस मामले में उस समय बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जब साल 2019 में केरल वक्फ बोर्ड ने जमीन को वक्फ संपत्ति के रूप में रजिस्टर्ड कर दिया. इसके बाद पहले की गई बिक्री को अवैध माना गया, जिससे 600 से ज्यादा परिवारों को बेदखली का डर सताने लगा. इस फैसले के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए. वक्फ बोर्ड के इस कदम को कोझिकोड वक्फ ट्रिब्यूनल में चुनौती दी गई, जहां मामला अब भी पेंडिंग है. विवाद और बढ़ते तनाव के बीचनवंबर 2024 में केरल सरकार ने समाधान तलाशने के लिए पूर्व न्यायाधीश जस्टिस सी.एन. रामचंद्रन नायर की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया. इसके खिलाफ केरल वक्फ संरक्षण वेदी ने हाईकोर्ट का रुख किया और तर्क दिया कि वक्फ एक्ट से जुड़े मामलों में राज्य सरकार को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है. हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने इस दलील को स्वीकार करते हुए आयोग को रद्द कर दिया था.

वक्फ के दावे के बाद शुरू हुआ विवाद

हालांकि, बाद में अक्टूबर 2025 में केरल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकल न्यायाधीश के फैसले को पलट दिया. डिवीजन बेंच ने न केवल जांच आयोग को वैध ठहराया, बल्कि यह भी टिप्पणी की कि 2019 में वक्फ बोर्ड द्वारा जमीन का पंजीकरण कानून के विपरीत था. अदालत ने कहा कि 1950 का दस्तावेज वक्फनामा नहीं बल्कि गिफ्ट डीड है, और जमीन को वक्फ घोषित करना जमीन पर कब्जे की रणनीति जैसा प्रतीत होता है. हाईकोर्ट की इन टिप्पणियों को चुनौती देते हुए केरल वक्फ संरक्षण वेदी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट ने यह तय कर दिया कि जमीन वक्फ है या नहीं, जबकि यह मामला पहले से ही वक्फ ट्रिब्यूनल में लंबित है. साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि हाईकोर्ट का फैसला कार्यपालिका को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप की छूट देता है, जहां कानून के तहत अलग वैधानिक प्रक्रिया निर्धारित है. हिंदुस्तान में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, संक्षिप्त सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया, जमीन की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया और जांच आयोग को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति दी है. मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी 2026 को होगी. फिलहाल कब्जाधारियों और वक्फ अधिकारियों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं.

‘मुसलमान मुझे किडनी दे देंगे, लेकिन वोट नहीं’, असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का बड़ा दावा

आवाज़ ए तसनीम

असम में अगले साल विधानसभा चुनाव 2026 होने हैं. इस बीच, राज्य की राजनीति पहले से ही गरमा गई है और असम सरकार पर मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि हिमंत बिस्वा सरमा सरकार पर इल्ज़ाम है कि ज़्यादातर मुस्लिम इलाकों में बुलडोजर चलवाए हैं. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने साफ-साफ कहा है कि अगर वह मुसलमानों को दस हज़ार रुपये या एक लाख रुपये भी दे दें, तो भी वे उन्हें वोट नहीं देंगे.

निजी न्यूज चैनल के एक प्रोग्राम में उनसे पूछा गया था कि क्या वह बिहार में नीतीश कुमार की 10 हजार रुपये की स्कीम का ह्रष्ठ पर जो चमत्कारी असर हुआ, उसे देखते हुए ऐसी ही कोई स्कीम शुरू करने पर विचार कर रहे हैं. इस सवाल के जवाब में सरमा ने कहा कि बिहार में ह्रष्ठ की जीत सिर्फ़ महिलाओं को दिए गए 10 हजार रुपये की वजह से नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के अच्छे शासन की वजह से हुई. हालांकि उन्होंने माना कि यह भी एक वजह थी, लेकिन सभी ने 10 हजार रुपये के लिए वोट नहीं दिया.

मुसलमान कभी नहीं देंगे वोट

उन्होंने साफ़-साफ़ कहा कि अगर लोगों ने 10 हजार रुपये के लिए वोट दिया होता, तो मुसलमान भी उन्हें वोट देते. अगर मैं उन्हें एक लाख रुपये भी दे दूं, तो भी मुस्लिम समुदाय वोट नहीं देगा. उन्होंने यह भी कहा कि यह एक बात है, लेकिन यह भी एक बड़ा सवाल है. हर किसी को 10 हजार रुपये नहीं मिले, फिर भी उन्हें इतने वोट कैसे मिले? उन्होंने मुसलमानों पर आरोप लगाया कि पैसे मिलने पर भी उन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया. सीएम ने कहा, अगर मैं उन्हें अभी एक लाख रुपये भी दे दूं, तो भी असम में उनमें से एक बड़ा हिस्सा मुझे वोट नहीं देगा. अगर मैं अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को एक लाख रुपये भी दे दूं और वे मुझसे कहें कि सीएम बहुत अच्छे हैं, तब भी वे मुझे वोट नहीं देंगे.

मुसलमान मुझे किडनी दे देंगे लेकिन वोट नहीं...

असम के सीएम ने आगे एक घटना याद करते हुए कहा कि जिन मुसलमानों की उन्होंने मदद की है, वे मानते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर वे उन्हें किडनी दे देंगे, लेकिन वे उन्हें वोट नहीं देंगे. उन्होंने कहा, एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, आपने मेरी इतनी मदद की है कि ज़रूरत पड़ने पर मैं आपको किडनी भी दे दूंगा, लेकिन मैं आपको वोट नहीं दूंगा. उन्होंने आगे कहा कि वोट पूरी तरह से आइडियोलॉजी पर डाले जाते हैं, पैसे या किसी स्कीम के आधार पर नहीं. अगर ऐसा होता, तो तेजस्वी यादव ज़्यादा सीटें जीतते.

Asian Youth Para Games 2025: बिना हाथों के रचा इतिहास; रतलाम के कादिर ने दुबई में भारत को दिलाए 3 गोल्ड

आवाज़ ए तसनीम

मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के होनहार दिव्यांग तैराक अब्दुल कादिर ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि हौसले अगर मजबूत हों तो कोई भी शारीरिक कमी रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती. दुबई में आयोजित एशियन यूथ पैरा गेम्स में अब्दुल कादिर ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए कई पदक जीते और अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रौशन किया.

अब्दुल कादिर की ऐतिहासिक उपलब्धि की खबर के बाद जिले में खुशी की लहर दौड़ गई. उनके परिजनों ने कहा कि कादिर की यह उपलब्धि रतलाम जिले के लिए गर्व और सम्मान की बात है. अब्दुल कादिर ने इन खेलों में कुल चार पदक अपने नाम किए हैं, जिनमें तीन गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल शामिल है. उनके इस प्रदर्शन से न सिर्फ रतलाम बल्कि पूरे प्रदेश में खुशी और उत्साह का माहौल है.

प्रतियोगिता की शुरुआत में अब्दुल ने 50 मीटर बैकस्ट्रोक एस 1-5 स्पर्धा में शानदार तैराकी करते हुए स्वर्ण पदक जीता. इसके बाद उन्होंने 100 मीटर फ्री स्टाइल और 50 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धाओं में भी गोल्ड मेडल हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. वहीं, 50 मीटर बटरफ्लाई एस 2-7 स्पर्धा में अब्दुल कादिर ने कांस्य पदक जीतकर पदकों की संख्या चार तक पहुंचा दी.

खास बात यह है कि अब्दुल कादिर बिना हाथों के तैराकी करते हैं. इसके बावजूद उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन कर यह दिखा दिया कि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि जज्बे और मेहनत में होती है. आज अब्दुल कादिर हजारों नौजवानों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी न किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं.

रतलाम में अब्दुल कादिर की इस ऐतिहासिक सफलता को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. सोशल मीडिया पर लोग उनकी मेहनत, संघर्ष और जीत की कहानी की खुलकर तारीफ कर रहे हैं. हर कोई कादिर को बधाई दे रहा है और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहा है. अब रतलाम को अपने इस स्वर्णिम सितारे का बेसब्री से इंतजार है. जानकारी के मुताबिक, अब्दुल के रतलाम पहुंचते ही उनका भव्य स्वागत किया जाएगा. शहर में उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करने की भी तैयारी की जा रही है और पूरे रतलाम में जश्न का माहौल बनने की उम्मीद है.

मौलाना तौकीर रज़ा को मिली राहत, बरेली हिंसा में कोर्ट ने दिया बेल

आवाज़ ए तसनीम

बरेली में I Love Muhammad अभियान के तहत हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़प हुई थी. इसके बाद पुलिस ने इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा को गिरफ्तार कर लिया. अब कोर्ट ने मौलाना तौकीर रज़ा को 1 लाख रुपये के बॉन्ड के साथ कंडिशनल बेल दे दी है.

दरअसल, गुरुवार 11 दिसंबर को बरेली के स्थानीय कोर्ट ने बरेली हिंसा मामले में तौकीर रज़ और एक और व्यक्ति को कंडिशनल बेल दी है. कोर्ट ने दोनों को एक-एक लाख रुपये का बॉन्ड भी भरने को कहा है.

इस कंडीशनल बेल में कोर्ट ने यह शर्त लगाई है कि आरोपी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की परमिशन के बिना शहर नहीं छोड़ पाएंगे. साथ ही अगर वे जांच में सहयोग नहीं करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को यह अधिकार प्राप्त है कि आरोपियों की बेल खारिज करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सके.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इत्तेहाद-ए-मिल्लत के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को अब तक चार केस में बेल मिल चुकी है. हालांकि उनपर अभी 6 अन्य केस चल रही हैं. बता दें कि बीते 26 सितंबर को I Love Muhammad के अभियान के तहत मुस्लिम समाज के लोगों ने बरेली में प्रोटेस्ट किया, लेकिन पुलिस ने इस प्रोटेस्ट को रेकने की कोशिश की. देखते ही देखते पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस ने बेरहमी के साथ प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लाठियां भाजी, जिसे दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए. वहीं, पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी पुलिस पर हमला किया गया. इस हिंसक झड़प के बाद पुलिस ने 19 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया, वहीं, 55 अन्य अज्ञात पर भी मुकदमा दर्ज किए गए. पुलिस ने 38 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट की. बता दें कि बरेली हिंसा के बाद पुलिस के साथ अन्य विभागों ने कार्रवाई तेज कर दी. साथ ही लगातार बुलडोजर कार्रवाई भी की गई. खास कर बुलडोजर की कार्रवाई मौलाना तौकीर रज़ा के करीबियों और रिश्तेदारों के कथित अवैध संपत्तियों के खिलाफ की गई.

न ट्रेनिंग न कोई कम्पटीशन और 90 हज़ार तक सैलरी, मदरसा शिक्षकों की नियुक्ति पर सरकार की गिद्ध दृष्टि!

आवाज़ ए तसनीम

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मदरसे लगातार सरकार के निशाने पर हैं. गैर-पंजीकृत मदरसों और कथित तौर पर सरकारी ज़मीन में बने सैकड़ों मदरसों पर बुल्डोज़र चलाकर ढहाने या उसपर ताला लगाने के बाद अब सरकार की नज़र सरकारी मदरसों में होने वाली शिक्षक भर्ती की प्रक्रियाओं पर है. राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओपी राजभर ने 7 दिसम्बर को बहराइच में एक अवामी खिताब में कहा था कि सरकारी मदरसों के सिलेबस में NCERT, ICSC और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निसाब शामिल करने के साथ ही वहां होने वाली शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं में सरकार बदलाव करने जा रही है. राजभर ने कहा है कि सरकारी मदरसों में शिक्षकों की भर्ती अब आयोग के जरिये की जायेगी जैसा की आम तौर पर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की भर्तियाँ होती हैं. राजभर के इस बयान के दो दिन बाद 9 दिसम्बर को ही अल्पसंख्यक कल्याण के निदेशक और मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार ने सभी जिले के अल्पसंख्यक अफसरान को 3 दिन के अंदर मदरसा शिक्षकों की जानकारी मांगी है.सरकार ने इस आदेश में 29 मई 2025 को विधानसभा हाउस में हुई उस ऑडिट रिपोर्ट की बैठक का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया था कि मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति में बड़े पैमाने पर धांधली की खबरें सामने आयी हैं. सरकारी मदरसों में प्रबंधन ने मदरसा नियमवाली 2016 का उल्लंघन कर अपने रिश्तदारों की नियुक्तियां की है.

मदरसों को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि सभी मदरसों में मैनेजमेंट कमिटी इस बात का हलफनामा देंगे कि उनके मदरसे में सभी नियुक्तियां मदरसा नियमावली 2016 के तहत की गई है, और कमिटी के किसी भी नजदीकी रिश्तेदारों को नियुक्त नहीं किया गया है.

सरकार के इस आदेश के बाद एक बार फिर मदरसा संचालकों के साथ ही मुस्लिम समाज इस बात से डर गया है कि सरकार नए बहाने से सरकारी मदरसों का अनुदान बंद करने, मान्यता रद्द करने या फिर उसमें अपने लोग थोपने की कोशिश करेगी. इस तरह मदरसों के संचालन में सरकार दखल देने का काम करेगी.

अगर ऐसा होगा तो उत्तर प्रदेश के 560 सरकारी मदरसे और वहां पढ़ाने वाले लगभग 8,400 सरकारी मदरसा शिक्षकों के भविष्य पर संकट पैदा हो सकता है.

मदरसों में अभी कैसे हो रही है नियुक्ति ?

सरकारी मदरसों में 5 सदसीय कमिटी की सिफारिश पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नियुक्ति करता है, और फिर उस फाइनल नाम पर मदरसा बोर्ड मुहर लगाता है. इस कमिटी में एक मदरसा का अध्यक्ष, एक सेक्रेट्री, प्रिंसिपल और दो बाहर के लोग होते हैं. आम तौर पर अध्यक्ष की सहमति पर सेक्रेट्री ही शिक्षकों के नाम की फाइल लिस्ट जिला माइनॉरिटी ऑफिसर (ष्ठरूह्र) को भेजता है. हालांकि, इस नियुक्ति में मदरसा नियमावली 2016 का पालन करना ज़रूरी होता है, जिसमें साफ़- साफ़ कहा गया है कि मदरसा प्रबंधन समिति के 5 सदस्यों में से किसी भी सदस्य के नजदीकी किसी रिश्तेदारों की नियुक्ति शिक्षक के तौर पर नहीं की जायेगी.

मदरसों का स्तर और शिक्षकों की योग्यता

आमतौर पर मदरसे चार स्तर के होते हैं. कक्षा पहली से लेकर पांचवी यानी प्राइमरी तक, जिसे तहतानिया कहा जाता है. कक्षा 6 से 8 माध्य या मिडिल, जिसे फौकानिया कहा जाता है. कक्षा 9 से 10 माध्यमिक या हाई स्कूल, जिसे आलिया कहा जाता है. कक्षा 11 से 12 उच्चतर माध्यमिक या हायर सेकंड्री, इसे उच्च आलिया कहा जाता है. कुछ मदरसों में कामिल और फ़ाज़िल की भी पढाई हो रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 1 जून 2025 को इसपर ये कहते हुए इसपर रोक लगा दी कि कोई स्कूल और स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कैसे करा सकता है, और डिग्री कैसे दे सकता है. ये उच्च शिक्षण संस्थाओं को नियमन करने वाली संस्था ह्रष्ट के नियमों के खिलाफ है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि कामिल और फाजिल की पढ़ाई, सिलेबस और इसकी डिग्री के लिए इन पाठ्यक्रमों को किसी यूनिवर्सिटी से जोड़ा जाए.सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से प्रदेश में एक साथ 34 हज़ार विद्यार्थी प्रभावित हुए थे, जो कामिल और फाजिल की पढाई कर रहे थे. हालांकि, प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने उस वक़्त कहा था कि कामिल और फाजिल की डिग्रियों की बुनियाद पर सरकारी नौकरी कर रहे किसी भी कर्मचारी की नौकरी पर कोई आंच नहीं आएगी.

मदरसा शिक्षकों की योग्यता

मदरसों में शिक्षकों की भर्ती का बैसिक पैमाना वो ही है जो स्कूलों में होता है, लेकिन यहाँ शिक्षण प्रशिक्षण की अनिवार्यता नहीं रखी गई है.कक्षा पहली से लेकर पांचवी यानी तहतानिया में 10 वीं पास आदमी, कक्षा 6 से 8 मिडिल या फौकानिया में इंटर पास और कक्षा 9 से 10 आलिया और कक्षा 11 से 12 उच्चतर माध्यमिक या उच्च आलिया में कामिल और फ़ाज़िल पास आदमी टीचर बन सकता है. इन सभी के साथ ये शर्त रखी जाती है कि वो विषय के रूप में उर्दू, अरबी और फ़ारसी का अध्ययन कर चुके हों.इसमें किसी यूनिवर्सिटी से पास ग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट भी शिक्षक बनने के पात्र होते हैं. लेकिन हमेशा मदरसे से फारिग (शिक्षित) उमीदवारों को तरजीह दी जाती है. चूंकि, आजतक किसी मदरसे में कामिल(ग्रेजुएशन) और पोस्ट ग्रेजुएशन शिक्षकों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की भर्ती ही नहीं हुई तो, निम्न कक्षा में पढ़ाने वाले शिक्षक ही उन्हें पढ़ा रहे थे.

सरकारी मदरसा शिक्षकों का वेतनमान

कक्षा 1 से लेकर 5 तहतानिया के शिक्षकों को (4200), कक्षा 6 से 8 फौकानिया को (4600), कक्षा 9 से 10 आलिया और उच्च आलिया यानी उच्चतर माध्यमिक के शिक्षकों को (4800) पेय ग्रेड वाला वेतनमान दिया जाता है. 7वां वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद 4200 पे ग्रेड वाले प्राइमरी मदरसा शिक्षकों की सैलरी 35000 से 1, 12000 तक हो सकती है. इनकी इन्हैंड सैलरी 45 से 60 हज़ार के बीच होती है. फौकानिया 4600 पे बैंड वालों की सैलरी 45 हज़ार से 1 लाख 12 हज़ार तक हो सकती है. इनकी इन्हैंड सैलरी 60 हज़ार तो हो सकती है. वहीँ उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों की 4800 पे ग्रेड की सैलरी 47 हज़ार से शुरू होती है जो 1 लाख 22 हज़ार तक जाती है.इनके हाथ में 80 से 90 हज़ार तक आते हैं. लखनऊ में एक बड़े मदरसे के संचालक याकूब कुरैशी कहते हैं, सरकारी मदरसों में नौकरी मिलने के बाद अच्छा वेतनमान मिलता है, जबकि नौकरी लेना उतना मुश्किल नहीं है, जितना एक स्कूल का शिक्षक बनना है. यहाँ अभी भी बीएड या बीटी जैसे शिक्षक प्रशिक्षण की डिग्री की अनिवार्यता नहीं है. मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति में भाई-भातीजाबाद के आरोपों पर आल इंडिया मदरसा टीचर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मोहम्मद सगीर आलम कहते हैं।

सचिन तेंदुलकर ने लियोनल मेसी को वर्ल्डकप जर्सी गिफ्ट की

फुटबॉलर ने मुंबई में तिरंगा थामा, दर्शकों में फुटबॉल फेंकी; बॉलीवुड सितारों से भी मिले

आवाज़ ए तसनीम

अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी भारत में 3 दिन के ‘GOAT इंडिया’ टूर पर हैं। दौरे के दूसरे दिन उन्होंने मुंबई में क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर से मुलाकात की। सचिन ने वानखेड़े स्टेडियम में उन्हें अपना नाम लिखी हुई टीम इंडिया की वर्ल्ड कप जर्सी गिफ्ट की।

मेसी शाम करीब 5.30 बजे वानखेड़े स्टेडियम पहुंचे। यहां उन्होंने साथी खिलाड़ी लुईस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल के साथ अर्जेंटीना और भारत का झंडा भी थामा। साथ ही मेसी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बॉलीवुड के सितारों से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ फुटबॉल खेला और दर्शकों में फुटबॉल भी फेंकी।

मेसी ने छेत्री को जर्सी गिफ्ट की

मेसी ने मुंबई में सुआरेज और डी पॉल के साथ पैडल इवेंट में हिस्सा लिया। वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर से ही दर्शकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। शाम करीब 5.30 बजे भारत के दिग्गज फुटबॉलर सुनील छेत्री वानखड़े स्टेडियम पहुंचे। यहां उन्होंने इंडियन स्टार्स और मित्र स्टार्स टीम के साथ फ्रेंडली मैच खेला। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ भी मैच खेलते नजर आए। मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा।

शाम करीब 6 बजे सचिन तेंदुलकर और मेसी वानखेड़े स्टेडियम पहुंचे। मेसी यहां छेत्री से मिले और उन्हें मोमेंटो और जर्सी भी गिफ्ट की। कुछ देर बाद मेसी ने पेनल्टी शूटआउट में हिस्सा लिया। इस दौरान फैंस ने बार्का (मेसी के पिछले क्लब बार्सिलोना) के नारे लगाए।

सचिन तेंदुलकर के साथ लियोनल मेसी, लूईस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल। सचिन तेंदुलकर के साथ लियोनल मेसी, लूईस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल। शूटआउट के बाद मेसी ने मैदान का चक्कर लगाया और दर्शकों में फुटबॉल फेंकी। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ फुटबॉल भी खेला। आखिर में मेसी ने महाराष्ट्र के ष्टरू देवेंद्र फडणवीस, बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और एक्ट्रेस करीना कपूर से भी मुलाकात की। इस दौरान सचिन ने मेसी को अपनी 2011 वनडे वर्ल्ड कप की जर्सी गिफ्ट की।

मदरसा शिक्षा के पीछे पड़ने वाले से सुप्रीम कोर्ट नाराज़; चेतावनी देकर लगाया 1 लाख का जुर्माना

आवाज़ ए तसनीम

सुप्रीम कोर्ट ने आज मदरसों और माइनॉरिटी कम्युनिटी द्वारा चलाए जा रहे दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर राइट टू एजुकेशन (ऋञ्जश्व) एक्ट लागू करने की मांग वाली एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में पिटीशनर को कड़ी फटकार लगाई.जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और आर. महादेवन की बेंच ने न सिर्फ पिटीशन सुनने से मना कर दिया, बल्कि पिटीशनर पर 1 लाख रुपये का भी जुर्माना लगाया.

बेंच ने साफ तौर पर कहा कि पिटीशनर ने 2014 के सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के फैसले (प्रमथी एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया) को गैर-कानूनी तरीके से चैलेंज करने की कोशिश की थी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि ऋञ्जश्व एक्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पर लागू नहीं होता है. कोर्ट ने कहा, ÷आप रिट पिटीशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज नहीं कर सकते. ऐसी पिटीशन ज्यूडिशियरी की नींव को कमजोर करने की कोशिश हैं. हम पिटीशनर पर 1 लाख रुपये का फाइन लगा रहे हैं, लेकिन इसे कंटेम्प्ट केस बनने से रोकने तक ही खुद को लिमिटेड रख रहे हैं.

याचिकाकर्ता ने किया बड़ा दावा

यह पिटीशन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 के तहत फाइल की गई थी. इसमें मांग की गई कि ऋञ्जश्व एक्ट का सेक्शन 12(1)(ष), जो प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए 25 परसेंट रिज़र्वेशन जरूरी करता है, उसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पर भी लागू किया जाए. पिटीशनर ने दावा किया कि ‘प्रमाति’ फैसले की वजह से बड़ी संख्या में बच्चों को डाइवर्सिटी और इनक्लूजन के माहौल में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के उनके फंडामेंटल राइट से दूर रखा जा रहा है.

पिटीशनर का बड़ा आरोप

पिटीशनर ने यह भी आरोप लगाया कि कई माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कमर्शियल बेसिस पर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं, जबकि कमजोर बच्चों को शामिल करने की अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल ज़िम्मेदारी से बचते हैं. उनके मुताबिक, यह प्रैक्टिस आर्टिकल 14, 15(4), और 21 का साफ उल्लंघन है और आर्टिकल 30(1) के तहत माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को दी गई ऑटोनॉमी का गलत इस्तेमाल है.

इससे पहले भी कोर्ट सुना चुका था फैसला

इससे पहले अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट की एक और दो-जजों की बेंच ने चीफ जस्टिस को एक PIL भेजी थी जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाने वाले सभी स्कूलों (माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन सहित) में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) को ज़रूरी बनाने की मांग की गई थी.

توانائی کا تحفظ آج کی سب سے اہم ضرورت: دروپدی مرمو

قومی توانائی تحفظ ایوارڈ اور قومی مصوری مقابلہ انعامات کی تقسیم۔تقریب سے صدر جمہوریہ کا خطاب

آوازِ تسنیم

صدرِ جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ ایک متوازن ماحولیاتی نظام کو برقرار رکھنے کے لئے صاف ہوا اور محفوظ آبی ذرائع بھی بے حد اہم ہیں۔انہوں نے کہا کہ ہم جتنی زیادہ توانائی کا تحفظ اور بچت کریں گے، وہ فطرت کے تئیں ہماری ذمہ داری اور آنے والی نسلوں کے تئیں ہماری حساسیت کی علامت ہوگی۔مرمو نے اتوار کے روز یہاں 'یوم قومی تحفظ توانائی' کے موقع پر قومی توانائی تحفظ ایوارڈ اور قومی مصوری مقابلہ انعامات کی تقسیم کی تقریب میں یہ بات کہی۔صدر جمہوریہ نے کہا کہ ماحول دوست اور قابلِ اعتماد طریقے سے توانائی کا تحفظ ہی توانائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔توانائی کا تحفظ محض ایک انتخاب نہیں، بلکہ آج کی سب سے اہم ضرورت ہے۔انہوں نے زور دے کر کہا کہ تحفظ توانائی کا مطلب صرف کم استعمال کرنا نہیں، بلکہ توانائی کو سمجھ داری، ذمہ داری اور مہارت کے ساتھ استعمال کرنا بھی ہے۔انہوں نے کہا کہ جب ہم بجلی کے آلات کے غیر ضروری استعمال سے بچتے ہیں، توانائی مؤثر آلات اپناتے ہیں، اپنے گھروں اور کام کی جگہوں پر قدرتی روشنی اور ہواداری کا استعمال کرتے ہیں یا شمسی اور قابلِ تجدید توانائی کے ذرائع اپناتے ہیں، تو ہم نہ صرف توانائی بچاتے ہیں، بلکہ کاربن کے اخراج میں بھی کمی لاتے ہیں۔صدر جمہوریہ نے اس بات پر زور دیا کہ توانائی کا تحفظ آج کی سب سے اہم ضرورت ہے۔اگر نوجوان اور بچے توانائی کے تحفظ کے تئیں باخبر ہو کر اس سمت میں کوشش کریں تو اس میدان میں اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں اور ملک کی پائیدار ترقی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔صدرِ جمہوریہ نے کہا کہ سستی اور صاف توانائی تک رسائی برادریوں کو بااختیار بناتی ہے۔یہ مقامی معیشت کو فروغ دیتی ہے اور ترقی کے نئے مواقع پیدا کرتی ہے۔اسی لیے سبز توانائی صرف بجلی کی پیداوار تک محدود نہیں، بلکہ یہ بااختیاری اور ہمہ گیر ترقی کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔انہوں نے کہا کہ یہ جان کر خوشی ہو رہی ہے کہ 'پردھان منتری سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا' اور 'نیشنل گرین ہائیڈروجن مشن' جیسی پہلیں حیاتی ایندھن پر انحصار کو کم کر رہی ہیں۔اس کے ساتھ ساتھ حکومت قابلِ تجدید توانائی کے استعمال کی ذمہ داری اور پیداوار سے منسلک ترغیبی اسکیموں کے ذریعے قابلِ تجدید توانائی کو اپنانے اور توانائی کی کارکردگی کو بھی فروغ دے رہی ہے۔انہوں نے کہا کہ 2023-24ء میں ہندوستان کی توانائی مؤثریت کی کوششوں کے نتیجے میں 5.36 کروڑ ٹن تیل کے برابر توانائی کی بچت ہوئی۔انہوں نے کہا کہ ان کوششوں کے باعث سالانہ نمایاں معاشی بچت ہو رہی ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں بھی خاصی کمی آئی ہے۔صدر جمہوریہ نے کہا کہ ہندوستان کے توانائی تغیر (انرجی ٹرانزیشن) کی کامیابی کے لئے ہر شعبے اور ہر شہری کی شمولیت ضروری ہے۔تمام شعبوں میں توانائی کی مؤثریت لانے کے لئے رویوں میں تبدیلی بے حد ضروری ہے۔فطرت کے ساتھ ہم آہنگی قائم کر کے متوازن طرزِ زندگی اپنانے کا جذبہ ہندوستان کی ثقافتی روایت کی بنیادی اساس ہے۔یہی جذبہ دنیا کے لئے ہمارے پیغام ''لائف اسٹائل فار انوائرنمنٹ۔لائف'' کی بنیاد بنتا ہے۔انہوں نے توانائی کے تحفظ کے شعبے میں کام کرنے والے تمام شراکت داروں کی ستائش کی اور کہا کہ ان کا تعاون آنے والی نسلوں کے لئے ایک صحت مند اور روشن مستقبل کو یقینی بنائے گا۔

مرشدآباد کی بابری مسجد کے کیوآر کوڈ کا بے جا استعمال، پولیس میں شکایت

آوازِ تسنیم

معطل ترنمول کانگریس رکن اسمبلی ہمایوں کبیر کی فاؤنڈیشن نے ہفتہ کے دن الزام عائد کیا کہ مغربی بنگال کے ضلع مرشدآباد میں بابری مسجد جیسی مسجد بنانے عطیات کی وصولی کے لئے جو کیوآر کوڈ جاری کیا گیا اس کا بعض نامعلوم افراد نے بے جا استعمال کیا ہے۔ہمایوں کبیر کی ویسٹ بنگال اسلامک فاؤنڈیشن آف انڈیا کا دعویٰ ہے کہ ڈپلیکیٹ کیوآر کوڈ کے ذریعہ فراڈ ہوا ہے۔مغربی بنگال پولیس سائبر کرائم یونٹ میں شکایت درج کرادی گئی ہے۔میڈیا سے بات چیت میں بھرت پور کے رکن اسمبلی ہمایوں کبیر نے الزام عائد کیا کہ مبینہ فراڈ میں ریجی نگر کے ٹی ایم سی رکن اسمبلی ربیع العالم چودھری کا ہاتھ ہے۔انہوں نے کہا کہ میں نے پتہ چلالیا کہ یہ کس نے کیا ہے۔ربیع العالم چودھری کے حامیوں نے یہ کیا ہے۔بہتر ہوگا کہ پولیس کارروائی کرے ورنہ میرے پاس کارروائی کرنے کی طاقت ہے۔میں اس بینک کو بھی نہیں چھوڑوں گا جہاں پیسہ جمع ہوا ہے۔چودھری نے الزام کی تردید کی اور کہا کہ فراڈ میرے آدمیوں نے کیا ہے یا کسی اور نے ہم چاہتے ہیں کہ ہمایوں کبیر ثابت کریں۔وہ تاحال مجھ پر بے بنیاد الزامات عائد کر رہے ہیں۔غور طلب ہے کہ مجوزہ مسجد کے لئے تقریباً 3.5 کروڑ روپے جمع ہو گئے ہیں۔11 بکسوں میں ڈالی گئی رقم کی گنتی چہارشنبہ کی رات مکمل ہوگئی۔اس کے علاوہ کیوآر کوڈ سے آن لائن عطیات بھی موصول ہوئے۔اسی کیوآر کوڈ کے تعلق سے فاؤنڈیشن کا الزام ہے کہ اس کا بے جا استعمال ہوا ہے۔

مودی حکومت کو اب مہاتما گاندھی سے بھی نفرت

باپائے قوم سے موسوم اسکیم کا نام بدلنے پر کانگریس کی سخت تنقید

آوازِ تسنیم

مہاتما گاندھی نیشنل رورل ایمپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ (منریگا) کا نام بدلنے کو کابینہ کی منظوری کے بعد کانگریس نے ہفتہ کے دن کہا کہ مودی حکومت اسکیموں کا نام بدلنے میں ''ماہر'' ہے۔اس نے پوچھا کہ مہاتما گاندھی کے نام میں کیا برائی تھی جو یہ قدم اٹھانا پڑا۔کانگریس جنرل سکریٹری جے رام رمیش نے کہا کہ مودی حکومت اسکیموں اور قوانین کا نام بدلنے میں ماہر ہے۔اس نے نرمل بھارت ابھیان کو سوچھ بھارت ابھیان اور رورل ایل پی جی ڈسٹری بیوشن پروگرام کو اُجولا کا نام دے دیا۔یہ حکومت ازسرنو پیکیجنگ اور برانڈنگ کی ماہر ہے۔وہ پنڈت نہرو سے نفرت کرتی ہے لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ مہاتما گاندھی سے بھی چڑ ہے۔مہاتما گاندھی کے نام میں کیا برائی تھی۔

منریگا کا نام بدل کر پوجیہ باپو ایمپلائمنٹ گارنٹی اسکیم کیوں رکھا گیا۔مرکزی کابینہ نے جمعہ کے دن بل کو منظوری دی جس کی رو سے اب یہ اسکیم پوجیہ باپو گرامین روزگار یوجنا کہلائے گی اور اس کے تحت ایامِ کار 100 دن سے بڑھا کر 125 دن کردیئے گئے۔کانگریس جنرل سکریٹری انچارج تنظیمی امور کے سی وینوگوپال نے کہا کہ جس پردھان منتری نے منریگا کو کبھی ناکامی کا پہاڑ کہا تھا وہ اب اس کا نام بدل رہا ہے تاکہ انقلابی اسکیم کا کریڈٹ لے سکے۔آئی اے این ایس کے بموجب کانگریس رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی وڈرا نے ہفتہ کے دن سوال اٹھایا کہ منریگا کا نام بدلنے کی کیا ضرورت تھی۔انہوں نے کہا کہ نام بدلنے کی مشق پر غیر ضروری سرکاری خرچ ہوگا اور عوام کو اس کا کوئی ٹھوس فائدہ نہیں پہنچے گا۔پرینکا گاندھی نے کہا کہ نام بدلنے کی منطق ان کی سمجھ سے باہر ہے۔یہ بڑا فلاحی پروگرام 2005 میں بنا تھا اور تقریباً 20 برس سے چل رہا ہے۔

☆☆☆

اپوزیشن کی خطرناک ذہنیت بے نقاب: شہزاد پونا والا

کانگریس کی ریالی میں مودی کیخلاف نعروں پر بی جے پی ترجمان کا شدید ردعمل

آوازِ تسنیم

کانگریس کی آج دہلی کے رام لیلا گراؤنڈ پر احتجاجی ریالی کے دوران وزیراعظم نریندر مودی کے خلاف لگائے گئے قابل اعتراض نعروں پر شدید ردعمل ظاہر کرتے ہوئے بی جے پی کے ترجمان شہزاد پونا والا نے الزام لگایا کہ ریالی نے اپوزیشن کی خطرناک ذہنیت کو بے نقاب کردیا اور درحقیقت یہ ریالی انتخابی امور کے لئے منعقد نہیں کی گئی تھی۔انہوں نے کہا کہ نعروں سے یہ بات ظاہر ہوگئی کہ یہ احتجاج جمہوری ایجی ٹیشن کے بجائے دستوری اقدار پر حملہ کے لئے منعقد کیا گیا تھا۔یہ بات واضح ہے کہ یہ ریالی ایس آئی آر کے بارے میں نہیں تھی۔درحقیقت یہ دستور پر حملہ تھا اور اس کا مقصد خاندان کو بچانا تھا۔ان متنازعہ ریمارکس کا حوالہ دیتے ہوئے جو کہ کانگریس قائدین کی جانب سے مبینہ طور پر کئے گئے، انہوں نے مزید کہا کہ جب کہ دستور پر حملہ کرتے ہوئے اب ایک ویڈیو منظر عام پر آیا ہے جس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک کانگریس لیڈر مبینہ طور پر کانگریس ہائی کمان کی ایماء پر وزیراعظم کی ہلاکت کے بارے میں بات کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی قبر جلد یا بدیر کھودی جائے گی۔جس سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ ان لوگوں کا مقصد پی ایم مودی کا صفایا کرنا ہے کیونکہ ان کے لئے خاندانی حکمرانی دستوری جمہوریت سے بالاتر ہے۔شہزاد پونا والا نے کانگریس پر بار بار جارحانہ اور اشتعال انگیز کارروائیوں میں ملوث رہنے کا بھی الزام لگایا۔حال ہی میں راگنی نائک نے وزیراعظم مودی کا ایک اے آئی ویڈیو بنایا اور اس کا مذاق اڑایا۔بہار میں ایک انتخابی ریالی کے دوران وزیراعظم کی ماں کو برا بھلا کہا گیا اور راہول گاندھی نے پارلیمنٹ میں دستوری اداروں جیسے الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دیں۔ان کی شہ پر پارٹی کارکنوں نے وزیراعظم مودی کو دھمکیاں دیں۔انہوں نے الزام لگایا ''یہ ای ایم آئی: اندرا کے پوتے کی ایمرجنسی ذہنیت ہے۔''

بی جے پی ووٹ چوری کے ذریعے حکومتیں بنا کر جمہوریت کو کمزور کر رہی ہے

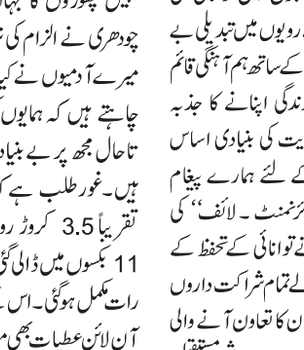

دہلی میں 'ووٹ چور' گدی چھوڑ' ریالی سے چیف منسٹر ہماچل سکھویندر سنگھ سکھو کا خطاب

آوازِ تسنیم

ہماچل پردیش کے چیف منسٹر سکھویندر سنگھ سکھو نے اتوار کو بی جے پی پر الزام عائد کیا کہ وہ ''ووٹ چوری'' کے ذریعے حکومتیں بنا کر جمہوریت کو کمزور اور عوام کے ووٹ کی طاقت کو کھوکھلا کر رہی ہے۔رام لیلا میدان میں منعقدہ ''ووٹ چور، گدی چھوڑ'' میگا ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ملک میں ''ووٹ چوری'' کی اجازت نہ دیں۔انہوں نے کہا کہ کانگریس، ریالی میں موجود عوامی طاقت کے زور پر، ایسی بدعنوانیوں کو روکے گی۔سکھو نے کہا کہ جب ملک میں 78 سال قبل جمہوریت قائم ہوئی تو اس کی سب سے بڑی طاقت یہ تھی کہ ہر شہری کو ووٹ کا حق دیا گیا۔انہوں نے کہا کہ کئی برسوں تک کانگریس نے انتخابات جیتے بھی اور ہارے بھی، مگر عوام کے ووٹ کی طاقت کو محفوظ رکھا۔انہوں نے کہا، ''اگر کسی نے عوام کے ووٹ کی طاقت کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ بی جے پی ہے۔اگر کسی جماعت نے اس جمہوریت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے جسے کانگریس نے محفوظ رکھا، تو وہ بی جے پی ہی ہے۔'' چیف منسٹر نے کہا کہ جب راہل گاندھی نے ''ووٹ چور، گدی چھوڑ'' کا نعرہ دیا تو اس کا مقصد عوام کے حقوق کا تحفظ تھا، جہاں حکومتیں ''ووٹ چوری'' اور جمہوریت کی خرید و فروخت کے ذریعے بنائی جا رہی تھیں۔انہوں نے کہا، ''بی جے پی اس طرح جمہوریت کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ہم یہاں اس عظیم ریلی میں موجود عوام کی طاقت سے ملک میں جمہوریت کو بچائیں گے۔'' کانگریس کے جنرل سکریٹری رندیپ سرجے والا نے کہا کہ پارٹی نے اس ''ووٹ چوری'' کے خلاف پورے ملک سے عام لوگوں کے تقریباً چھ کروڑ دستخط جمع کیے ہیں۔پارٹی صدر ملکارجن کھڑگے، کانگریس پارلیمانی پارٹی کی چیئرپرسن سونیا گاندھی اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہول گاندھی سمیت دیگر سینئر رہنما بھی اس ریلی میں موجود تھے۔

برندا کرت کا صدر جمہوریہ مرمو کو مکتوب

اخلاق لنچنگ کیس میں مداخلت کرنے کا مطالبہ

آوازِ تسنیم

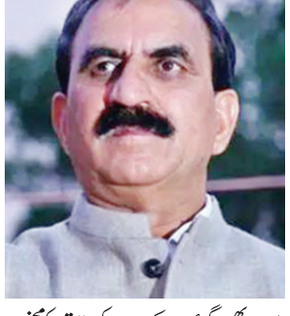

اخلاق لنچنگ کیس میں سینئر سی پی آئی (ایم) رہنما برندا کرات نے ہفتہ کے روز صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو خط لکھ کر اتر پردیش حکومت کی جانب سے الزامات واپس لینے کے اقدام میں مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔خط میں برندا کرات نے 2015 میں محمد اخلاق کی بھیڑ کے ہاتھوں ہلاکت کے معاملے میں ملزمین کے خلاف مقدمہ واپس لینے کے فیصلے کو حکومت کا ''سیاسی محرکات پر مبنی'' قدم قرار دیا اور اس معاملے میں گورنر کے کردار پر بھی سوال اٹھایا۔انہوں نے لکھا، ''میں آپ کی فوری توجہ اتر پردیش کے گورنر کے کردار کی جانب مبذول کرانا چاہتی ہوں، جو ستمبر 2015 میں پیش آنے والے محمد اخلاق کے لنچنگ کیس سے متعلق ہے۔گورنر نے تحریری اجازت دے کر اتر پردیش حکومت کو اس مکمل طور پر غیر قانونی اور ناانصافی پر مبنی اقدام کی اجازت دی ہے، جس کے تحت انصاف کے عمل کو سبوتاژ کرتے ہوئے پورا مقدمہ واپس لیا جا رہا ہے، حالانکہ مرکزی گواہ پہلے ہی اپنے شواہد پیش کر چکا ہے۔'' انہوں نے کہا کہ حکومت نے گورنر کی اجازت سے گریٹر نوئیڈا کی ضلع عدالت میں مقدمہ واپس لینے کے لیے حلف نامہ داخل کیا ہے۔برندا کرات نے کہا، ''مجھے افسوس ہے کہ مجھے اس معاملے میں آپ کو لکھنا پڑ رہا ہے، لیکن چونکہ گورنر آپ کے مقرر کردہ ہیں اور آپ کو جواب دہ ہیں، اس لیے میں نے انصاف کے مفاد میں حقائق سے آگاہ کرنا اور آپ سے فوری مداخلت کی درخواست کرنا ضروری سمجھا۔'' انہوں نے یاد دلایا کہ 28 ستمبر 2015 کو اتر پردیش کے بسہڑا گاؤں میں اخلاق کے گھر کے باہر ایک بھیڑ جمع ہوئی، جب ایک مقامی مندر سے یہ اعلان کیا گیا کہ اس نے گائے ذبح کی ہے۔اخلاق اور اس کے بیٹے دانش کو گھر سے گھسیٹ کر باہر نکالا گیا اور ان پر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں اخلاق کی موت ہو گئی۔کرات نے کہا، ''آج بھی دانش مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو سکا اور اس پر لگنے والے شدید زخموں کے اثرات اب تک موجود ہیں۔'' سی پی آئی (ایم) رہنما کے مطابق مقتول کی بیٹی نے عدالت میں بیان دیا اور تمام ملزمین کی نشاندہی کی۔انہوں نے کہا، ''یعنی ملزمین کے خلاف شواہد عدالت میں پیش اور ریکارڈ کیے جا چکے ہیں۔مقدمہ جاری ہے اور دو دیگر عینی گواہوں کے بیانات ابھی ہونے ہیں۔'' خط میں کہا گیا، ''ایسے وقت میں اتر پردیش حکومت نے نہایت ناقابلِ دفاع بنیادوں پر مقدمہ واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے، جیسے یہ دلیل دینا کہ لاٹھیاں استعمال ہوئیں، بندوقیں نہیں، مقتول کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، اور یہ کہ مقدمہ جاری رکھنے سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی متاثر ہوگی وغیرہ۔'' برندا کرات نے الزام لگایا کہ استغاثہ نے گواہوں کو طلبی کے نوٹس جاری نہ کر کے مقدمے میں تاخیر کی، اور اب اسی تاخیر کو مقدمہ واپس لینے کی بنیاد بنایا جا رہا ہے۔انہوں نے کہا، ''یہ اقدام انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے نہیں بلکہ پورے عدالتی عمل کو سبوتاژ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔''

میسی ایونٹ میں بدنظمی کی عدالتی نگرانی میں جانچ کا مطالبہ

ریاستی حکومت کی کمیٹی ناقابل قبول۔بی جے پی لیڈر سویندو ادھیکاری کا بیان

آوازِ تسنیم

مغربی بنگال میں قائد اپوزیشن اور بی جے پی کے رکنِ اسمبلی سُویندو ادھیکاری نے اتوار کو ایک روز قبل سالٹ لیک اسٹیڈیم میں ارجنٹائنی فٹبالر لیونل میسی کے ایونٹ کے دوران پیدا ہونے والی بدنظمی کی عدالتی نگرانی میں تحقیقات کا مطالبہ کیا۔پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ادھیکاری نے کہا کہ بی جے پی اسٹیڈیم میں پیش آئے واقعات کی جانچ کے لیے ریاستی حکومت کی مقرر کردہ کمیٹی کو قبول نہیں کرتی۔انہوں نے کہا، ''ہم اس کمیٹی کو قبول نہیں کرتے۔صرف حاضر سروس ججوں کی نگرانی میں ہونے والی تحقیقات ہی سچ سامنے لا سکتی ہیں۔'' ادھر مغربی بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی نے ہفتہ کے روز کولکاتا میں میسی کے فٹبال ایونٹ کو متاثر کرنے والی بدنظمی کی جانچ کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی کی تشکیل کا اعلان کیا تھا۔ادھیکاری نے ریاستی وزرا سُجیت بوس اور آروپ بسواس کی گرفتاری کا بھی مطالبہ کیا، ان پر ''بدانتظامی'' کا الزام لگایا اور شائقین کی جانب سے ادا کی گئی ٹکٹ کی رقم کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ادھیکاری کے دعووں پر ردِعمل دیتے ہوئے ترنمول کانگریس کے ترجمان آروپ چکرورتی نے کہا کہ ریاستی وزیر کھیل بسواس کو ایونٹ میں مدعو کیا گیا تھا، اور انہوں نے سوال اٹھایا کہ بی جے پی رہنماؤں کے اہلِ خانہ وہاں کیوں موجود تھے۔ادھیکاری نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ واقعے کے سلسلے میں درج ایف آئی آر کا مقصد چیف منسٹر اور دیگر ٹی ایم سی وزرا کے اہلِ خانہ کو تحفظ دینا تھا۔میسی کا شہر کا مختصر دورہ اُس وقت بدنظمی میں بدل گیا جب دنیا کے مقبول ترین فٹبالر کی صرف 22 منٹ کی جھلک نہ دیکھ پانے پر مشتعل شائقین نے ہفتہ کے روز سالٹ لیک اسٹیڈیم میں سکیورٹی ضوابط توڑ دیے۔بی جے پی رہنما کے ساتھ چند شائقین بھی موجود تھے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ ایونٹ میں شریک تھے اور مبینہ بدانتظامی کا شکار ہوئے۔ادھیکاری نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ بوتل بند پانی، جو ابتدا میں اسٹیڈیم کے اندر لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔بعد میں احاطے کے اندر کیسے فروخت ہوا، اور یہ کہ 150 سے 200 روپے کے درمیان قیمت پر چپس فروخت کرنے کی اجازت کس نے دی۔انہوں نے پوچھا، ''ان اشیا کو اسٹیڈیم کے اندر کس نے اجازت دی اور ان انتظامات سے کون پیسہ کما رہا تھا؟'' ادھیکاری نے کہا کہ چیف منسٹر ایونٹ میں شرکت کے لیے سالٹ لیک اسٹیڈیم جا رہی تھیں، مگر مقام پر بدنظمی پھیلنے کے بعد انہیں واپس لوٹنا پڑا۔انہوں نے اسے ''بے مثال'' قرار دیا۔

جوان افراد کی اچانک موت اور کوویڈ-19 ٹیکہ اندازی میں کوئی تعلق نہیں

اموات کی دیگر وجوہات۔ایمس کی ایک سالہ اسٹڈی کے نتائج

آوازِ تسنیم

آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس ایمس (اے آئی آئی ایم ایس) نئی دہلی کی جانب سے ایک سال تک لاشوں کا تنقیدی تجزیہ کیا گیا جس میں اس بات کا کوئی سائنٹفک ثبوت نہیں ملا کہ کوویڈ 19 کی ٹیکہ اندازی کا جوان بالغ افراد کی اچانک موت سے کوئی تعلق ہے۔اس طرح اس بات کی دوبارہ توثیق ہوئی ہے کہ یہ ٹیکے محفوظ اور موثر ہیں۔Testiary care centre in India میں ایک سال تک کی گئی اسٹڈی انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کے جرنل میں شائع ہوئی ہے۔محققین نے 18 اور 45 سال عمر والوں کی اچانک موت کے کیس کا گہرائی سے جائزہ لیا اس تحقیق میں وربل آٹوپسی، پوسٹ مارٹم امیجنگ کنونشنل آٹوپسی اور تفصیلی ہسٹو پیتھالوجیکل ٹسٹس کا استعمال کیا گیا۔اس اسٹڈی کے جو نتائج سامنے آئے اس کے بموجب کوویڈ-19 ٹیکہ اندازی اور جوان بالغ افراد کی اچانک موت کے درمیان اعداد و شمار کے لحاظ سے کوئی نمایاں تعلق نہیں تھا۔محققین کے بموجب ان میں بیشتر اموات کی وجوہات دیگر بیماریاں تھیں جیسے قلب میں دوران خون کی شریانوں کی بیماریاں بڑی وجہ بن کر سامنے آئیں۔کئی کیسس میں تنفس اور دیگر بیماریوں کی نشاندہی ہوئی جن کا تعلق قلب سے نہیں تھا۔اسٹڈی میں یہ بھی دیکھا گیا کہ کوویڈ-19 انفیکشن اور ٹیکہ اندازی کی صورتحال جوانوں اور زیادہ عمر کے گروپ سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر یکساں نوعیت کی تھی اور ٹیکہ اندازی اور اچانک اموات میں کوئی اتفاقی ربط نہیں پایا گیا۔اے آئی آئی ایم ایس نئی دہلی کے پروفیسر ڈاکٹر سدھیر اراوا نے کہا کہ خصوصاً ایسے وقت جبکہ کوویڈ-19 ٹیکہ اندازی اور اچانک اموات کے درمیان امکانی تعلق کے بارے میں گمراہ کن دعوے اور غیر مصدقہ اطلاعات پھیلائے جا رہے ہیں یہ اسٹڈی اہمیت کی حامل ہوجاتی ہے۔ماہرین نے صحت کے معائنوں طرز زندگی میں تبدیلیوں اور بروقت علاج کی اہمیت کو اجاگر کیا تاکہ اس طرح کے خطرات کو کم کیا جا سکے۔

جوگڈول قتل کیس، این ایچ آر سی سے مداخلت کی درخواست

16 سال بعد بھی متاثرین انصاف سے محروم۔آسام کی سیول سوسائٹی تنظیم کا مکتوب

آوازِ تسنیم

آسام میں گوہاٹی کے کامروپ ضلع کے مقامی سیول سوسائٹی تنظیم نے سوناپور میں جوگڈول قتل کیس کے متاثرین کے لئے انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے قومی انسانی حقوق کمیشن (این ایچ آر سی) سے مداخلت کی درخواست کی ہے۔یہ واقعہ 12 دسمبر 2009 کی رات کو پیش آیا، جب ایک غریب قبائلی تیوا خاندان کے چھ افراد کا بے دردی سے سرقلم کر دیا گیا تھا۔ڈیموریا واکاس منچ کے چیف ایڈوائزر دویہ جیوتی میدھی نے کہا کہ 16 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی کامروپ (میٹرو) ضلع کے ڈیموریا قبائلی علاقے میں سوناپور تھانے کے تحت پیش آئے اس ہولناک واقعہ میں انصاف نہیں ملا ہے۔میدھی نے کمیشن کو اپنی درخواست میں کہا کہ ''متاثرین۔ہرکانت ڈولوئی، اہلیہ سوپنا ڈولوئی، ان کی بیٹیاں پرنیتا ڈولوئی اور سبیتا ڈولوئی، بیٹا اتل ڈولوئی اور ان کا بھتیجا توکل ڈولوئی۔ان کا تعلق ایک غریب قبائلی خاندان سے تھا جن کی کوئی دشمنی نہیں تھی۔ہرکانت ڈولوئی ایک معمولی کسان تھے اور انتہائی غریب خاندان میں رہتے تھے۔انہوں نے الزام لگایا کہ سوناپور پولیس کی ابتدائی تفتیش منصفانہ نہیں تھی جو شاید آسام کے ایک سابق وزیر کی مشتبہ ملوثی سے متاثر تھی۔میدھی نے مزید کہا، ''یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ قتل کے بعد متاثرین کے گھروں کو جلانے سمیت اہم شواہد کو تباہ کر دیا گیا تھا۔مرکزی ملزم ارجن بوردولوئی کو 5 ستمبر 2012 کو اس کے گھر کے سامنے پراسرار حالات میں قتل کر دیا گیا تھا، جس سے تحقیقات کی غیر جانبداری پر مزید شکوک پیدا ہو گئے تھے۔'' انہوں نے کہا کہ کئی برسوں سے مقامی نسلی اور سماجی تنظیموں کی جانب سے متعدد احتجاج اور یادداشتوں کے باوجود حکام نے کوئی جواب نہیں دیا ہے۔بعد ازاں کیس کو کرمنل انویسٹی گیشن ڈیپارٹمنٹ (سی آئی ڈی) کو منتقل کر دیا گیا۔7 دسمبر 2017 کو دو پولیس افسران، پرنب کمار ڈیکا، سوناپور پولیس کے اس وقت کے آفیسر انچارج، اور اے ایم۔چوہدری، تفتیشی افسر کو اصل مجرموں کو بچانے کیلئے جان بوجھ کر شواہد کو تباہ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔اپنی درخواست میں، میدھی نے کمیشن سے کیس میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لینے اور متاثرین کو انصاف دلانے کے لیے منصفانہ، آزاد اور بروقت تحقیقات کو یقینی بنانے کے لیے مداخلت کی اپیل کی۔

حکومت سے مالی امداد کیلئے انسانی حقوق کمیشن کی مداخلت کا حکم

کشی نگر میں انصاف کے لئے بھٹکتی مالا کو قرض سے نجات اور زمین واپس مل جانے کی اُمید

آوازِ تسنیم

اتر پردیش کے ضلع کشی نگر کے گاؤں جنگل کھرکیا میں آج بھی ایک بند گھر، اس پر رکھی لکڑیوں کا بوجھ اور اندر پھیلا سناٹا ایک دردناک کہانی بیان کرتا ہے۔یہ کہانی شیلیش مُسہر کی مشتبہ موت کے بعد ان کی اہلیہ مالا دیوی کی ہے، جو شوہر کے جانے کے بعد نہ صرف سہارا کھو بیٹھیں، بلکہ روزی روٹی، زمین اور عزت نفس کے لیے جدوجہد کرنے پر مجبور ہوگئیں۔اب تقریباً ایک سال بعد نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن (این ایچ آر سی) کے حکم نے مالا کی زندگی میں انصاف کی شمع روشن کی ہے۔ضلعی انتظامیہ کے مطابق، کشی نگر کے جنگل کھرکیا گاؤں کے رہائشی شیلیش مسہر کی 17 ستمبر 2024 کی رات مشتبہ حالات میں موت ہوگئی تھی۔اس وقت مالا دیوی پر گویا دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔وہ بتاتی ہیں کہ شوہر کی موت کے بعد گاؤں میں رہنا مشکل ہو گیا۔گھر کو تالا لگا کر اور باہر لکڑیوں کا ڈھیر لگا کر وہ ترک پٹی تھانہ علاقے کے بھنولی کوٹھی گاؤں میں اپنے بھائی ناگیندر کے گھر چلی گئیں۔تب سے وہ کبھی کبھار ہی اپنے گاؤں آتی ہیں۔مالا بتاتی ہیں کہ ان کے نام 17 کٹھہ زمین ہے، لیکن شوہر کے علاج اور قرض کے بوجھ کی وجہ سے اسے 70 ہزار روپے میں رہن رکھنا پڑا۔انہیں یہ تک معلوم نہیں تھا کہ شوہر کی موت کے معاملے میں حکومت کی جانب سے کوئی امداد بھی مل سکتی ہے۔جب انہیں بتایا گیا کہ این ایچ آر سی کے حکم سے مالی مدد ملنے کا امکان ہے، تو ان کی آنکھوں میں امید کی نئی چمک اٹھی۔انہوں نے کہا کہ اگر پیسے مل گئے تو وہ رہن رکھی ہوئی زمین دوبارہ حاصل کرلیں گی۔دیہی باشندوں کے مطابق شیلیش کی موت کے بعد مالا گاؤں میں ٹک نہیں سکیں۔وہ اپنے دونوں بچوں کرشنا اور انکش کو لے کر بھائی کے گھر رہنے لگیں۔ان کا کہنا ہے کہ جب شوہر ہی نہیں رہے تو وہ کس کے سہارے یہاں رہتیں۔اس معاملے کی تہہ میں مائیکرو فنانس کمپنیوں کا قرض بتایا جا رہا ہے۔اطلاعات کے مطابق مالا نے چھ مائیکرو فنانس کمپنیوں سے تقریباً 2.30 لاکھ روپے کا قرض لیا تھا۔قرض کو لے کر گاؤں کے ہی ایک خاندان سے تنازعہ ہوا، جو بعد میں مار پیٹ تک پہنچ گیا۔مار پیٹ کے بعد شیلیش کی طبیعت بگڑ گئی اور انہیں ضلع اسپتال لے جایا گیا، جہاں ان کی موت ہوگئی۔پوسٹ مارٹم کے بعد جب 19 ستمبر 2024 کو شیلیش کی لاش گاؤں پہنچی، تو حالات مزید خراب ہوگئے۔دیہی باشندوں نے ملزمین کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے آخری رسومات سے انکار کر دیا اور دھرنے پر بیٹھ گئے۔تقریباً چار گھنٹے تک جاری رہنے والے دھرنے کے بعد انتظامی حکام کی یقین دہانی پر آخری رسومات ادا کی جا سکیں۔اس معاملے میں پڈرونا کوتوالی پولیس نے چار افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔تقریباً ایک سال کی سماعت کے بعد نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن نے 4 دسمبر کو کشی نگر کے ضلع مجسٹریٹ کو ایس سی/ایس ٹی (انسداد ظلم و زیادتی) رولز، 2016 کے تحت متاثرہ خاندان کو مالی امداد دینے کا حکم دیا ہے۔کمیشن نے چھ ہفتوں کے اندر حکم کی تعمیل کی رپورٹ بھی طلب کی ہے۔تاہم ابھی مقامی انتظامیہ کو اس حکم کی کاپی موصول نہیں ہوئی ہے۔اس سلسلے میں کشی نگر کے ضلع سماجی بہبود افسر رماشنکر یادو نے بتایا کہ حکم کے مطابق مقررہ رقم انہیں فراہم کردی جائے گی۔

हसीना के बयान से बौखलाई बांग्लादेश सरकार, भारत के सामने दर्ज कराई शिकायत; जानें क्या है मामला?

आवाज़ ए तसनीम

पड़ोसी मुल्क में मोहम्मद युनूस की अंतरिम सरकार के आने बाद भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक स्तर पर तनाव बढ़ता जा रहा है. बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने इतवार (14 दिसंबर) को भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब कर अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयानों को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है. बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना के बयानों को भड़काऊ करार दिया है और भारत सरकार के सामने इसे गंभीर चिंताजनक बताया है.

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय उच्चायुक्त को एक खास संदेश देने के लिए बुलाया गया है. बांग्लादेशी अधिकारियों के मुताबिक, उच्चायुक्त के जरिये भारत सरकार को स्पष्ट रूप से संदेश दिया गया है कि भगोड़ी शेख हसीना को भारत में रहते हुए ऐसे बयान देने की इजाजत देना बांग्लादेश की आंतरिक सुरक्षा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है.

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, शेख हसीना अपने समर्थकों से बांग्लादेश में कथित तौर पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आह्वान कर रही हैं. मंत्रालय का कहना है कि इन बयानों का मकसद बांग्लादेश में होने वाले आगामी संसदीय चुनावों को रूकावट डालना है. बता दें, 78 वर्षीय शेख हसीना अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए हिंसक छात्र-नेतृत्व वाले प्रदर्शनों के बाद देश छोड़कर भारत चली गई थीं. तब से वह भारत में ही रह रही हैं. पिछले महीने बांग्लादेश की एक विशेष ट्रिब्यूनल ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी.

बांग्लादेश की युनूस सरकार लगातार पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के लगातार प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है. विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में दोहराया कि शेख हसीना को जल्द से जल्द बांग्लादेश को सौंपा जाए ताकि वह विशेष ट्रिब्यूनल के जरिये सुनाई गई सजा का सामना कर सकें. इसके साथ ही बांग्लादेश ने पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल के प्रत्यर्पण की भी मांग दोहराई है. कमाल को भी पिछले महीने विशेष ट्रिब्यूनल ने मौत की सजा सुनाई थी.

बांग्लादेश सरकार का कहना है कि दोनों ही नेताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए उनका जल्द से जल्द प्रत्यर्पण बेहद जरूरी है. विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि भारत में रहते हुए शेख हसीना के कथित भड़काऊ बयान बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश है. सरकार का आरोप है कि इन बयानों का सीधा असर देश की सुरक्षा व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर पड़ सकता है.

शांति के ठेकेदार अमेरिका में नफरत का नंगा नाच, वर्जीनिया में मस्जिद से लौट रही मुस्लिम औरतों पर जानलेवा हमला

आवाज़ ए तसनीम

अमेरिका का शुमार दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में होता है. अमेरिकी राष्ट्रपति हमेशा दुनिया में अमन शांत कायम करने का दावा करते रहे हैं, लेकिन इसकी आड़ में वह कई मुस्लिम मुल्कों में हमले कर चुके हैं. हालांकि, अमेरिका अपने ही देश में रह रहे मुसलमानों को सुरक्षा देने में नाकाम रहा है. दक्षिणपंथी यहूदी और ईसाई ग्रुप्स लगातार मुसलमानों को निशाना बनाते रहे हैं. मुसलमानों से नफरत की यह आग अब वर्जीनिया में भी देखने को मिली.

दरअसल, वर्जीनिया स्टेट के फेयरफैक्स काउंटी में मौजूद एक मुस्लिम कम्यूनिटी सेंटर एक शख्स ने औरतों पर जानलेवा हमला कर दिया. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होती जा रही है. इस घटना को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. स्थानीय लोग और मानवाधिकार संगठनों ने मांग की है कि मुस्लिम कम्यूनिटी सेंटर पर हमला करने वाले आरोपी शख्स के खिलाफ हेट क्राइम (नफरत से जुड़ा अपराध) के तहत मामला दर्ज किया जाए. बताया जा रहा है कि हमला पहले भी इस मस्जिद में इबादत के लिए आने जाने वाले लोगों पर हमले कर चुका है. अब हालिया घटना बीते माह 28 नवंबर की बताई जा रही है, जब फेयरफैक्स काउंटी की दार अल नूर कम्युनिटी सेंटर में नमाज अदा करने के बाद बाहर निकल रही मुस्लिम औरतों के एक ग्रुप पर आरोपी ने हमला कर दिया. मस्जिद की ओर से जारी किए गए सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि आरोपी मुस्लिम औरतों को अपशब्द कहते हुए किसी हथियार से हमला कर रहा है.

आरोपी को देखकर पीड़ित औरतें डर के मारे वापस मस्जिद के अंदर चली गईं. मुस्लिम औरतों ने आरोपी को पीछ न हटने पर पुलिस को बुलाने की चेतावनी दी. इसके बाद आरोपी मस्जिद के बाहर लगे कैमरे की ओर हाथ मारते हुए और गालियां देते हुए नजर आता है. वीडियो में वह चिल्लाते हुए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करते हुए उन्हें मुसलमानों को यहां से निकल जाने की धमकी देता है.

पुलिस ने इस घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान डॉक्टर टोनी शियाओ के रूप में की है. पुलिस ने उस पर हमला करने, वैध रूप से परिसर में घुसने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के तहत मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस के मुताबिक, शियाओ को इससे पहले भी इसी तरह के आरोपों में पिछले साल गिरफ्तार किया जा चुका है.

हालांकि, अब तक आरोपी पर हेट क्राइम के तहत आरोप नहीं लगाए गए हैं. इस बात को लेकर मुस्लिम संगठनों और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई है. काउंसिल ऑन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशंस (CAIR) ने शुक्रवार को सार्वजनिक रूप से मांग की कि राज्य और संघीय अधिकारी आरोपी पर हेट क्राइम का मुकदमा दर्ज करें. CAIR के वकील अहमद काकी ने एक बयान में कहा कि संघीय अधिकारियों को आरोपी को पूरी तरह जवाबदेह ठहराना चाहिए और हेट क्राइम के तहत आरोप तय करने चाहिए. उन्होंने कहा कि किसी भी शख्स को एक ही इबादतगाह पर बार-बार हमला करने की छूट नहीं दी जा सकती. उनका कहना था कि यह साफ संदेश जाना चाहिए कि फेयरफैक्स काउंटी और पूरे देश में सभी मजहब के लोग सुरक्षित हैं. इस घटना के बाद फेयरफैक्स काउंटी स्थित दार अल नूर कम्युनिटी मस्जिद ने बयान जारी किया है. मस्जिद प्रशासन का कहना है कि यह दूसरी बार है जब इसी शख्स ने दार अल नूर मस्जिद को निशाना बनाया है. इस घटना के बाद स्थानीय मुस्लिम समुदाय में डर और चिंता का माहौल बना हुआ है.

बॉन्डी बीच का असली हीरो; अहमद ने आतंकी से हथियार छीन बचाईं कई बेगुनाहों की जानें

जब नफरत, हिंसा और आतंक का साया इंसानों को डर के मारे छिपने पर मजबूर कर दे, तब कोई निहत्था शख्स अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचा ले तो वह महज सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि इंसानियत की पहचान बन जाता है. ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर हुई भयावह गोलीबारी के दौरान 43 साल के अहमद अल अहमद ने वही कर दिखाया, जिसकी वजह से आज उन्हें पूरे दुनिया में 'हीरो' कहा जा रहा है.

इतवार (14 दिसंबर) को सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुई इस सामूहिक गोलीबारी की घटना को ऑस्ट्रेलिया में बीते कई सालों की सबसे घातक आतंकी घटनाओं में से एक बताया जा रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल एक 15 सेकंड के वीडियो में देखा जा सकता है कि अहमद अल अहमद गोलीबारी के दौरान मौके पर पार्क की गई कारों के पीछे छिपे थे. इस दौरान वह बिल्कुल निहत्थे थे.

उनसे महज कुछ दूरी पर एक आतंकी लगातार फायरिंग कर रहा था. उन्होंने मौके की नजाकत को भांपते हुए अपनी जान की परवाह किए बगैर दौड़ते हुए हथियारबंद हमलावर पर पिल पड़े. वीडियो में देखा जा सकता है कि अहमद ने हमलावर की गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया. इसके बाद उन्होंने हमलावर के हाथ से राइफल छीनी और उसी हथियार को उसकी ओर तान दिया. माना जा रहा है कि उनकी इस बहादुरी की वजह से कई बेगुनाहों की जान बच गई.

कौन हैं हीरो अहमद अल अहमद?

स्थानीय मीडिया आउटलेट सेवन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, अहमद अल अहमद पेशे से फल विक्रेता हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, इस हमले में अहमद को दो गोलियां लगीं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मीडिया से बातचीत में अहमद के चचेरे भाई मुस्तफा ने बताया कि अहमद अस्पताल में हैं और उनकी हालत को लेकर परिवार बेहद फिक्रमंद है. उन्होंने कहा, 'हमें नहीं पता अंदर क्या हो रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि वह ठीक हो जाएंगे. वह सौ फीसदी हीरो हैं.'

रिपोर्ट के मुताबिक, अहमद की उसी रात सर्जरी होनी थी. यह भी सामने आया है कि अहमद को हथियार चलाने का कोई अनुभव नहीं था और वह सिर्फ वहां से गुजर रहे थे, लेकिन हालात देखकर उन्होंने हस्तक्षेप करने का फैसला किया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अहमद की बहादुरी की जमकर तारीफ हो रही है. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने भी अहमद को हीरो करार दिया है.

12 लोगों के मौत की खबर

पुलिस के मुताबिक, इस आतंकी हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत हुई है. यह हमला बॉन्डी बीच पर उस समय हुआ जब यहूदी समुदाय के लोग हनुक्का उत्सव मना रहे थे. इस घटना में 29 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है. न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने बताया कि इस हमले में दो संदिग्ध शामिल थे. एक की मौत हो चुकी है, जबकि दूसरा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है.

ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने क्या कहा?

पुलिस ने पास में खड़े एक वाहन से विस्फोटक उपकरण भी बरामद कर उन्हें सुरक्षित रूप से हटा दिया. न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने इस हमले को आतंकवादी घटना घोषित किया है. इजराइल के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि मृतकों में एक इजराइली नागरिक भी शामिल है. प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि हमले के तुरंत बाद राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की आपात बैठक बुलाई गई. उन्होंने इसे यहूदी ऑस्ट्रेलियाई समुदाय पर टार्गेट हमला बताया है. उन्होंने कहा कि नफरत, हिंसा और आतंकवाद के लिए ऑस्ट्रेलिया में कोई जगह नहीं है.

बांग्लादेश में चुनाव से पहले सड़कों पर खूनी संघर्ष; ढाका के निर्दलीय प्रत्याशी को दिनदहाड़े मारी गोली, BNP ने बताया साजिश

आवाज़ ए तसनीम

बांग्लादेश में अगले साल फरवरी माह में आम चुनाव है. उससे पहले पूरे देश में चुनावी हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का माहौल लगातार गहराता जा रहा है. राजधानी ढाका में हाल ही में हुई गोलीबारी की घटना के बाद हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं. ढाका-8 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार शरीफ उस्मान हादी को गोली मार कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद यहां हालात और ज्यादा भयावह हो गए हैं.

इस घटना को लेकर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के सेक्रेटरी जनरल मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने गंभीर चिंता जताई है. इतवार (14 दिसंबर) को मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने आशंका जाहिर की कि शरीफ उस्मान हादी पर हुए हमले जैसी घटनाएं दोबारा भी हो सकती हैं. BNP नेता ने चेतावनी दी कि बांग्लादेश के दुश्मन एक बार फिर देश को अस्थिर करने की साजिश कर रहे हैं और इसके लिए टारगेट किलिंग जैसे तरीकों का सहारा लिया जा रहा है.

मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि जब बांग्लादेश एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है और देश के लोग एक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के जरिए एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था की उम्मीद कर रहे हैं, ठीक उसी समय इस तरह की हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं. उन्होंने कहा कि यह हालात देश को अस्थिर करने की सोची-समझी कोशिश की ओर इशारा करते हैं.

BNP नेता ने बताया कि उनकी पार्टी ढाका-8 के निर्दलीय उम्मीदवार शरीफ उस्मान हादी पर हुए हमले की कड़ी निंदा करती है. उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद यह डर पैदा हो गया है कि आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं फिर से हो सकती हैं. फखरुल ने यह बयान मीरपुर में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान दिया. गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने 13वें संसदीय चुनाव और रेफरेंडम के कार्यक्रम का ऐलान किया था. इसके ठीक एक दिन बाद शुक्रवार को ढाका में शरीफ उस्मान हादी को गोली मार दी गई. हमले में उन्हें सिर में गोली लगी, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. फिलहाल उनका इलाज ढाका के एवरकेयर हॉस्पिटल में चल रहा है.

इस दौरान मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने 14 दिसंबर के ऐतिहासिक महत्व का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान जब पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन फोर्स की हार तय हो चुकी थी और लिबरेशन वॉर फोर्स ने ढाका को घेर लिया था, तब पाकिस्तानी सेना और उसके सहयोगियों ने एक साजिश के तहत बांग्लादेश के प्रमुख बुद्धिजीवियों को निशाना बनाया.

फखरुल ने कहा कि उस समय विश्वविद्यालयों के शिक्षक, डॉक्टर, शोधकर्ता, लेखक, पत्रकार और कई अन्य पेशेवरों की योजनाबद्ध तरीके से हत्या की गई. उनका कहना था कि यह सब बांग्लादेश को बौद्धिक रूप से कमजोर करने के मकसद से किया गया था.

बता दें कि बांग्लादेश में हर साल 14 दिसंबर को शहीद बुद्धिजीवी दिवस मनाया जाता है. इस दिन 1971 में पाकिस्तानी सेना और उसके सहयोगियों द्वारा सैकड़ों बुद्धिजीवियों, डॉक्टरों, शिक्षकों, पत्रकारों और कलाकारों का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी गई थी ताकि नवगठित बांग्लादेश को एक मजबूत और स्वतंत्र राष्ट्र बनने से रोका जा सके.

इमरान खान की तन्हा कैद पर पूर्व पत्नी जेमिमा की पुकार, एलन मस्क से लगाई मदद की गुहार

आवाज़ ए तसनीम

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान लंबे समय से जेल में बंद है. इमरान खान की हिरासत के खिलाफ शहबाज शरीफ सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है. इमरान खान के साथ जेल में हो रहे कथित अत्याचार अब सिर्फ पाकिस्तान की घरेलू सियासत का मुद्दा नहीं रह गया है बल्कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का विषय बन चुका है.

एक दिन पहले इमरान खान की पहली बीवी जेमिमा खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क को टैग करते हुए मदद की अपील की गुहार लगाई थी. जेमिमा खान ने दावा किया कि इमरान खान को लंबे समय से अपने परिवार से मिलने और बातचीत करने की इजाजत नहीं दी जा रही है.

इसी बीच कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने पाकिस्तान सरकार पर आरोप लगाया है कि इमरान खान को जेल में लंबे समय तक अकेले रखा गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक मानसिक यातना की श्रेणी में आता है. संगठनों का कहना है कि किसी भी शख्स को लंबे समय तक एकांत में रखना न सिर्फ अमानवीय है बल्कि यह उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकता है.

पाकिस्तान को इस वक्त देश के भीतर आलोचना के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं और कानूनी समूहों की ओर से भी औपचारिक हस्तक्षेप का सामना करना पड़ रहा है. कई वैश्विक संगठनों और विशेषज्ञों ने इमरान खान को अकेले कैद में रखने और उन्हें कानूनी सलाह व मुलाकात से महरूम करने को लेकर इस्लामाबाद को एक संयुक्त चिट्ठी भेजी है.

इन संगठनों ने चेतावनी दी है कि एक चुने हुए पूर्व प्रधानमंत्री को इस तरह अलग-थलग रखना गंभीर लोकतांत्रिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल सकता है. इमरान खान की हिरासत को लेकर संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष रिपोर्ट में भी पाकिस्तान सरकार की कड़ी आलोचना की गई है. संयुक्त राष्ट्र की स्पेशल रिपोर्टर एलिस जिल एडवर्ड्स ने पाकिस्तान से अपील की है कि वह अमानवीय और अपमानजनक हिरासत से जुड़ी रिपोर्टों पर तुरंत और प्रभावी कार्रवाई करे. उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत किसी शख्स को लंबे समय तक या बिना किसी निगरानी के अकेले में रखना प्रतिबंधित है. एलिस जिल एडवर्ड्स ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर अकेले में रखे जाने की अवधि 15 दिनों से ज्यादा हो जाती है, तो इसे मनोवैज्ञानिक यातना माना जाता है. उन्होंने कहा कि इमरान खान की एकांत कैद को बिना देरी खत्म किया जाना चाहिए और इस तरह के व्यवहार से उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इमरान खान को लंबे समय तक अकेले रखना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का खुला उल्लंघन है और इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप जरूरी है. इस विवाद को उस समय और हवा मिली जब इमरान खान के करीबी सहयोगी और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री मुहम्मद सोहैब आफरीदी ने दावा किया कि जेल में खान के साथ खराब बर्ताव किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि अदियाला जेल प्रशासन ने इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी को दसवीं बार खान से मिलने की इजाजत नहीं दी है, जिससे पारदर्शिता और कानूनी पहुंच को लेकर सवाल और गहरे हो गए हैं. दूसरी ओर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सियासी मामलों के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इमरान खान से मुलाकात को इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर रोका गया था. सनाउल्लाह का आरोप है कि खान का इरादा 26 नवंबर को इस्लामाबाद में हुए विरोध प्रदर्शनों जैसे एक और आंदोलन की योजना बनाने का था. इस बीच इमरान खान के करीबी सहयोगी डॉ. सलमान अहमद ने खुले तौर पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर पर पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ गैरकानूनी कार्रवाई करने के आरोप लगाए हैं. वहीं, जेमिमा खान ने एक्स पर एलन मस्क को टैग करते हुए लिखा कि उनके दोनों बेटों ने लंबे समय से अपने पिता को नहीं देखा है. उन्होंने दावा किया कि महीनों से बच्चों को इमरान खान से बात करने या चिट्ठी भेजने की भी इजाजत नहीं दी गई है. जेमिमा ने यह भी कहा कि इमरान खान का नाम पाकिस्तान के लगभग सभी टीवी और रेडियो चैनलों से बैन कर दिया गया है और पाकिस्तानी अधिकारी उनके करीबी लोगों की आवाज दबाने को तरजीह दे रहे हैं.

इमरान खान पर जुल्म न करे पाकिस्तान सरकार, UN एक्सपर्ट ने की बड़ी मांग

आवाज़ ए तसनीम

पाकिस्तान के अदियाला जेल में पिछले दो वर्षों से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कैद हैं. जेल के अंदर उन पर जुल्म किए जाते हैं, इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है. UN एक्सपर्ट एलिस जिल एडवर्ड्स ने पाकिस्तान सरकार से इस रिपोर्ट पर ध्यान देने और तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है.

UN एक्सपर्ट एलिस जिल एडवर्ड्स ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की अमानवीय और अपमानजनक हिरासत से संबंधित रिपोर्ट पर तुरंत और असरदार कार्रवाई करने को कहा है. यह रिपोर्ट बीते शुक्रवार 12 दिसंबर को टॉर्चर पर ह एक्सपर्ट एलिस जिल एडवर्ड्स ने शेयर किया. एडवर्ड्स ने पाकिस्तानी अधिकारियों से यह पक्का करने की अपील की कि इमरान खान की हिरासत की शर्तें पूरी तरह से इंटरनेशनल नियमों और स्टैंडर्ड के हिसाब से हों.

उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अदियाला जेल में पिछले दो सालों से एकांत में रखा गया है, उन्हें दिन में 23 घंटे उनके सेल में बंद रखा जाता है, और बाहरी दुनिया तक उनकी पहुंच बहुत कम कर दी गई है. उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का सेल लगातार कैमरे की निगरानी में रहता है.

UN एक्सपर्ट एलिस जिल एडवर्ड्स ने इस बात पर जोर देकर कहा कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कानून के तहत लंबे समय तक अकेले रखना मना है. उन्होंने यह भी कहा कि जब यह कार्रवाई 15 दिनों से ज़्यादा हो जाता है, तो यह एक तरह का साइकोलॉजिकल टॉर्चर होता है.

UN एक्सपर्ट एलिस जिल एडवर्ड्स ने पाकिस्तान सरकार से मांग की है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की अकेलेपन की सजा बिना देर किए हटाई जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि इस प्रकार किसी को एकांत में रखना और सजा देना न सिर्फ गैर-कानूनी तरीका है, बल्कि लंबे समय तक अकेला रहने से उनकी शारीरिक और मानसिक सेहत पर बहुत बुरे असर पड़ सकते हैं.

परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं: केंद्रीय मंत्री श्री मेघवाल- एपेक्स हॉस्पिटल तथा कम्यूनिटी वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित

आवाज़ ए तसनीम

जयपुर, एपेक्स हॉस्पिटल तथा कम्यूनिटी वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को बेसिक इंग्लिश स्कूल परिसर में विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित हुआ।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल थे। मेघवाल ने कहा कि निरोगी काया ही सबसे बड़ा सुख है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे स्वस्थ रहेंगे, तो देश स्वस्थ रहेगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक देश को विकसित बनाने के संकल्प में सहायक सिद्ध होगा।मेघवाल ने एपेक्स हॉस्पिटल तथा कम्यूनिटी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्य की सराहना की और कहा कि परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। दूसरों की सेवा करने वाले व्यक्तियों को हमेशा याद रखा जाता है।कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी के संरक्षक राजकुमार किराडू ने स्वागत उद्बोधन दिया। उन्होंने समिति की गतिविधियों के बारे में कहा कि संस्था द्वारा 10 वर्षों से सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष राम गोपाल सुथार, शिक्षाविद नारायण व्यास, गुमान सिंह राजपुरोहित, कम्यूनिटी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष कन्हैया लाल भाटी और विजय आचार्य आदि अतिथि के रूप में रहे।कम्यूनिटी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा केंद्रीय मंत्री का अभिनंदन किया गया। तत्पश्चात केंद्रीय मंत्री ने मेडिकल शिविर का मुआयना किया तथा चिकित्सा सेवा में लगे चिकित्सकों की हौसला अफजाई की।

पटवार भर्ती परीक्षा 2025 सफल अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन— कुल 6284 ने कराया दस्तावेज सत्यापन, रविवार को 1175 अभ्यर्थी हुए उपस्थित

आवाज़ ए तसनीम

जयपुर पटवार भर्ती परीक्षा 2025 के तहत सफल रहे अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम के तहत रविवार को 1312 के मुकाबले 1116 व पूर्व में अनुपस्थित रहे 59 सहित कुल 1175 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन हुआ जबकि 196 अनुपस्थित रहे ।यह जानकारी देते हुए उप निबंधक (भू अभिलेख) रवीन्द्र कुमार ने बताया कि गत 8 दिसम्बर से आरंभ हुए दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम के तहत 7410 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था जिसमें से कुल 6 हजार 284 सफल रहे अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन कार्य पूरा किया जा चुका है जबकि कुल 1126 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।इस सप्ताह भर के कार्यक्रम के दौरान दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया का राजस्व मंडल अध्यक्ष श्री हेमन्त कुमार गेरा एवं निबन्धक महावीर प्रसाद द्वारा भी अवलोकन किया गया।

अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों के लिए सत्यापन का अंतिम अवसर—

इस प्रकार सत्यापन कार्य के अंतिम दिन तक दस्तावेज सत्यापन से वंचित रहे 1126 अभ्यर्थियों के लिए सोमवार, 15 दिसम्बर को दस्तावेज सत्यापन कराने का अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसकी सूचना राजस्व मंडल के पोर्टल पर मय रोल नंबर जारी की जा रही है। शेष रहे अभ्यर्थी आर आर टी आई अजमेर परिसर में 15 दिसम्बर को उपस्थित होकर इसका लाभ उठा सकते हैं।

अजमेर में बनेगा महर्षि दयानंद पैनोरामा

विधान सभा अध्यक्ष देवनानी ने की घोषणा, आर्य समाज मनाएगा स्वामी श्रद्धानंद की बलिदान शताब्दी

आवाज़ ए तसनीम

जयपुर। महर्षि दयानंद सरस्वती की निर्वाण स्थली अजमेर में अब दयानंद पैनोरमा बनेगा। इसे देखकर यहां आने वाले लोग महर्षि के महान जीवन से प्रेरणा ले सकेंगे। विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने रविवार को राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा के अजमेर स्थित ऋषि उद्यान में आयोजित सम्मेलन में यह घोषणा की। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वे प्रयास करेंगे कि आगामी बजट में ही दयानंद पैनोरामा के प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाए। देवनानी ने कहा कि सामाजिक जागृति में महर्षि दयानंद और आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान है। देवनानी ने कहा कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े काम किए हैं। इनमें केईएम का नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांति गृह करना, खादिम का नाम अजयमेरु करना शामिल है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के तारागढ़ पर बड़ी संख्या में अतिक्रमण हटाए गए हैं। इसे अब पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। देवनानी ने आर्य प्रतिनिधि सभा और आर्य वीर दल की अजमेर में आयोजित दो दिवसीय वार्षिक योजना समीक्षा बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधियों से संवाद करना और उनके समर्पण, अनुशासन व सेवा भावना को करीब से अनुभव करना अत्यंत सुखद व प्रेरणादायी रहा। कार्यक्रम को परोपकारिणी सभा के प्रधान ओम मुनि ने भी संबोधित किया। राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान जयसिंह गहलोत और मंत्री जीववर्धन शास्त्री ने देवनानी का शाल ओढ़ाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। परोपकारिणी सभा के न्यासी डॉ. वेदप्रकाश विद्यार्थी ने उन्हें आचार्य धर्मवीर की पुस्तक अग्नि सूक्त और भारतीय नारी भेंट की। कार्यक्रम का संचालन स्वामी ओमानंद सरस्वती ने किया।

वन राज्य मंत्री ने अलवर शहर विधानसभा कम्युनिटी क्रिकेट प्रतियोगिता का किया शुभारम्भ— विकास रथ का किया स्वागत, आमजन को प्रचार सामग्री की वितरित

आवाज़ ए तसनीम

जयपुर, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय शर्मा ने रविवार को अलवर सांसद खेल उत्सव 2.0 के तहत आयोजित अलवर शहर विधानसभा कम्युनिटी क्रिकेट प्रतियोगिता का राजऋषि महाविद्यालय के खेल मैदान में बैटिंग कर शुभारम्भ किया। इस दौरान उन्होंने प्रतियोगिता की ट्रॉफी का विमोचन भी किया।वन राज्यमंत्री श्री शर्मा ने मैच देखकर खिलाडियों की हौसला-अफजाई करते हुए टीम भावना के साथ खिलाडियों को खेल में अच्छा प्रदर्शन करने हेतु प्रोत्साहित किया। उन्होंने केंद्रीय वन मंत्री एवं अलवर सांसद श्री भूपेन्द्र यादव द्वारा खेल प्रतिभाओं को निखारने एवं उनको आगे बढाने के लिए अलवर सांसद खेल उत्सव के माध्यम से खेल का बेहतर प्लेटफार्म उपलब्ध कराने पर उनको साधुवाद दिया। उन्होंने कहा कि अलवर सांसद खेल उत्सव के माध्यम से ना केवल खिलाडियों को खेल मंच प्रदान किया जा रहा है, बल्कि खिलाडियों को सांई के प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण भी दिलाया गया है। उन्होंने कहा कि अलवर सांसद खेल उत्सव के तहत अलवर लोकसभा क्षेत्र की आठों विधानसभाओं में कम्युनिटी खेलों का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में खिलाडी बढचढकर उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अलवर शहर विधानसभा कम्युनिटी क्रिकेट प्रतियोगिता की ट्रॉफी का विमोचन भी किया।सरस डेयरी के चेयरमैन श्री नितिन सांगवान ने कहा कि अलवर के खिलाडियों की खेल प्रतिभा को निखार कर उन्हें खेल का बेहतर मंच प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्रीय वन मंत्री एवं अलवर सांसद श्री भूपेन्द्र यादव ने अलवर सांसद खेल उत्सव की शुरूआत की है।विकास रथ का किया स्वागत, आमजन को प्रचार सामग्री की वितरित—वन राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा ने राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आए विकास रथ का राजऋषि महाविद्यालय खेल मैदान में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अपने दो वर्षों में प्रदेश के चहुंमुखी विकास एवं आमजन के सर्वांगीण कल्याण की भावना से ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अपने दोनों बजटों में अलवर को विकास की महत्वपूर्ण सौगातें दी गई, जिससे अलवर के विकास को गति मिली है। उन्होंने आमजन से सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का जागरूक रहकर लाभ उठाने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने विकास रथ में लगी एलईडी स्क्रीन पर सरकार की योजनाओं के वीडियो संदेश को देखा तथा आमजन को प्रचार सामग्री वितरित की।

योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर आमजन ने किए अनुभव साझा—

राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आए विकास रथ का राजऋषि महाविद्यालय खेल मैदान में पहुंचने पर आमजन ने राज्य सरकार द्वारा विगत दो वर्षों के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों एवं सरकार द्वारा आमजन के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। अलवर शहर निवासी श्री सुरेन्द्र गुर्जर एवं दौलतराम शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर शहर के गली-मौहल्लों में जाकर सरकार की योजनाओं एवं दो वर्षों में किए गए कार्यों की महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी मिलने से इन योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा आमजन के हित में बहुत अच्छी-अच्छी योजनाएं संचालित की जा रही जिन्हें वीडियो संदेश के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। इससे आम आदमी को बहुत लाभ मिलेगा। कार्यक्रम का मंच संचालन पं. जलेसिंह ने किया।

सुशासन की दिशा में बढ़ते जयपुर जिला प्रशासन के कदम — स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत स्वच्छता एवं जन-जागरूकता श्रमदान कार्यक्रम — राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हुआ आयोजन

आवाज़ ए तसनीम

जयपुर, सुशासन की दिशा में जयपुर जिला प्रशासन के प्रयास लगातार जारी है। सुशासन सप्ताह से पहले वर्तमान सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 14 दिसंबर 2025 को राज्यव्यापी स्वच्छता एवं जन-जागरूकता अभियान के तहत प्रत्येक ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में जिला परिषद जयपुर के तत्वावधान में जिला स्तरीय स्वच्छता एवं श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन पंचायत समिति सांगानेर की ग्राम पंचायत महापुरा में किया गया।जिला स्तरीय कार्यक्रम में माननीय विधायक बगरू श्री कैलाश वर्मा, जिला प्रमुख श्रीमती रमा देवी चौपड़ा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद श्रीमती प्रतिभा वर्मा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री बृजमोहन गुप्ता, विकास अधिकारी श्रीमती ज्योति प्रजापति एवं सरपंच श्री हनुमान चौधरी की गरिमामयी उपस्थिति रही।कार्यक्रम के अंतर्गत जिला परिषद जयपुर के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सफाई कर्मियों द्वारा ग्राम पंचायत महापुरा स्थित राधा स्वामी मंदिर के समीप व्यापक साफ-सफाई एवं श्रमदान किया गया। इस दौरान कचरा, प्लास्टिक, पानी की बोतलें आदि एकत्र कर उन्हें हटाया गया तथा समस्त कचरे को आरआरसी **(RRC)** सेंटर भेजा गया।साफ-सफाई उपरांत उपस्थित सभी जनों द्वारा राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' का सामूहिक गायन किया गया। तत्पश्चात माननीय विधायक श्री कैलाश वर्मा द्वारा उपस्थित जनसमूह को स्वच्छता शपथ दिलाई गई।श्रमदान कार्यक्रम में जिला परिषद एवं पंचायत समिति के समस्त अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधिगण तथा स्थानीय नागरिकों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा स्वच्छता बनाए रखने, सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने तथा प्लास्टिक कचरे के उचित निस्तारण हेतु आमजन से अपील की गई।कार्यक्रम का उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों को सुदृढ़ करना तथा समाज में स्वच्छता के प्रति स्थायी जन-जागरूकता विकसित करना रहा।

राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर विशेष 2 सालः नव उत्थान - नई पहचान, बढ़ता राजस्थान - हमारा राजस्थान, सर्द मौसम में बेघरों के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संवेदनशील, प्रदेशभर में स्थाई एवं अस्थाई आश्रय स्थल बन रहे बेसहारों का सहारा, 138 नगरीय निकायों में लगभग 12 हजार व्यक्तियों की क्षमता के 238 स्थायी आश्रय स्थल हो रहे संचालित

आवाज़ ए तसनीम

जयपुर, राजस्थान में शीतलहर और सर्दी आम जनजीवन को प्रभावित कर रही है। कई शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया है। आगामी दिनों में सर्दी और बढ़ने के आसार हैं और यही मौसम की मार उन लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ती है, जिनके पास सर छुपाने को छत नहीं होती।मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य की डबल इंजन सरकार ऐसे जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक आश्रय देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में राजस्थान सरकार प्रदेश में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व में संचालित दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत, निर्मित स्थायी आश्रय स्थलों में शहरी बेघर व्यक्तियों को निःशुल्क आश्रय तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है।शीत लहर, बरसात और प्रचण्ड गर्मी के मौसम में प्रत्येक जरूरतमंद को आसरा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य के कुल 138 नगरीय निकायों में लगभग 12 हजार व्यक्तियों की क्षमता के 238 स्थायी आश्रय स्थल संचालित किए जा रहे है, जिनमें योजना के अनुरूप सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं जैसे स्वच्छ पानी, बिजली, शौचालय, रसोई, गीजर आदि उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके साथ ही कुल 109 नगरीय निकायों में आवश्यकतानुसार लगभग 9435 व्यक्तियों की क्षमता के 139 अस्थायी आश्रय स्थलों का संचालन भी किया जा रहा है। इन सभी अस्थायी आश्रय स्थलों में भी समस्त आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। राजस्थान के प्रत्येक नागरिक के बहुआयामी उत्थान व सर्वांगीण विकास के लिये मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रही अनेकों कल्याणकारी योजनाएं नर सेवा नारायण सेवा को चरितार्थ कर रही है।उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024 की शुरूआत में भी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए रैन बसेरों में रह रहे लोगों के बीच पहुंचकर उनकी कुशलक्षेम पूछी थी। साथ ही उन्होंने सड़कों पर रह रहे निराश्रित लोगों को कंबल भी वितरित किए थे।

विधानसभा अध्यक्ष ने अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र को तीन दिन में दी 6 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

आवाज़ ए तसनीम

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को नई गति देते हुए विगत तीन दिनों में लगभग 6 करोड़ रुपये की लागत के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी है। इन कार्यों के माध्यम से क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इससे आमजन को बेहतर आवागमन, सुचारू जल निकासी, पेयजल, सुरक्षा एवं स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाओं का प्रत्यक्ष लाभ मिल सकेगा। इसी क्रम में रविवार को देवनानी द्वारा नागफणी क्षेत्र में बद्री विशाल मंदिर के सामने आयोजित कार्यक्रम में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराए जाने वाले विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर वार्ड 5 में बद्री विशाल मंदिर से शास्त्री कॉलोनी तक नाले के निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस पर लगभग एक करोड़ 36 लाख 50 हजार रुपये की लागत आएगी। यह नाला वर्षों से चली आ रही जलभराव की समस्या एवं कच्चे नाले के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न परेशानियों के स्थायी समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस नाले का निर्माण कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण कराया जाएगा। नाले के निर्माण से नागफणी क्षेत्र के निवासियों को जलभराव से बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि अजमेर उत्तर क्षेत्र में अब तक लगभग 60 करोड़ रुपये की लागत से 15 नालों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसके सकारात्मक परिणामस्वरूप क्षेत्र धीरे-धीरे जलभराव की समस्या से मुक्त हो रहा है। इसके पश्चात देवनानी ने बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के अंतर्गत वार्ड 5 स्थित भागचंद सोनी नगर में स्वीकृत विभिन्न सड़क निर्माण कार्यों का भी शुभारंभ किया। इन सड़कों का निर्माण लगभग 16 लाख रुपये की लागत से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास की आधारशिला होती हैं। मजबूत सड़कें आवागमन को सुगम बनाने के साथ व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं दैनिक जीवन की गतिविधियों को भी गति प्रदान करती हैं। इन कार्यों के पूर्ण होने से वार्ड 5 की विभिन्न कॉलोनियों में आवागमन अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक होगा। इसी कड़ी में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा वार्ड 63 प्रताप नगर में भी विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। यहां पाबूदान सिंह जी के मकान से पुलिया तक सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इस पर 42 लाख रुपये की लागत आएगी। इसके साथ ही गोपाल सिंह क्लॉथ स्टोर से राजेश भाटी के मकान तक सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इसकी लागत 13 लाख रुपये निर्धारित है। इसके अतिरिक्त वार्ड 63 स्थित उद्यान में ओपन जिम, पाथ-वे एवं अन्य विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। इस पर लगभग 20 लाख रुपये की लागत से कार्य कराए जाएंगे। इन कार्यों से क्षेत्रवासियों को बेहतर यातायात सुविधा के साथ-साथ स्वास्थ्य एवं मनोरंजन से जुड़ी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पारदर्शिता एवं गुणवत्ता उनके कार्यों की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में तथा तय मानकों के अनुरूप पूर्ण किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि हाल के दिनों में सड़क एवं नाला निर्माण के साथ-साथ पेयजल परियोजनाओं, सुरक्षा से जुड़े कार्यों तथा महिलाओं की सुविधा के लिए पिंक टॉयलेट जैसे जनोपयोगी कार्यों पर प्राथमिकता के साथ करोड़ों रुपये व्यय कर विकास कार्य करवाए गए हैं। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

वर्तमान राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर विशेष नव उत्थान -नई पहचान बढ़ता राजस्थान- हमारा राजस्थान, राजस्थान उड्डयन प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र बनने की ओर अग्रसर- प्रदेश में 8 फ्लाइंग स्कूलों का होगा संचालन

2 साल
नव उत्थान - नई पहचान
बढ़ता राजस्थान - हमारा राजस्थान

आवाज़ ए तसनीम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार द्वारा उड्डयन के क्षेत्र में निरंतर कार्य किये जा रहे हैं। राज्य सरकार का सतत प्रयास है कि प्रदेश बेहतर एयर कनेक्टिविटी और अत्याधुनिक हवाई सुविधाओं के लिए देश-विदेश में अपनी पहचान बनाए। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान उड्डयन नीति लागू करना, नए फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूलों का संचालन, हवाई अड्डों का विस्तार और विकास करने जैसे तमाम फैसलों से राजस्थान हवाई सुविधाओं के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा।

प्रदेश में 8 नए फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूलों का संचालन

राजस्थान जल्द ही उड्डयन प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। किशनगढ़ और हमीरगढ़ में निजी फ्लाइंग ट्रेनिंग संस्थानों की स्थापना से राज्य में पायलट प्रशिक्षण और उड्डयन कौशल विकास की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण के नए अवसर उपलब्ध होंगे। राज्य में गत एक वर्ष में 8 फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूलों के संचालन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूलों के सुगम संचालन के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल पर टैक्स की दर 26 प्रतिशत से कम कर 2 प्रतिशत की गई है।राज्य के विभिन्न जिलों में हवाई पट्टियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इन हवाई पट्टियों को फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूलों के संचालन के लिए उपयोग में लाने का भी निर्णय लिया गया है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा नीति भी बनाई गई है। इसके तहत हवाई पट्टियों के साथ लगती हुई भूमि पर हैंगर स्थापित करने के लिए दरों का निर्धारण भी किया जाएगा।

नागरिक उड्डयन नीति से खुलेंगे निवेश के नए द्वार

राज्य सरकार द्वारा जारी राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति के तहत नए हवाई अड्डों के विकास को प्राथमिकता देने के साथ ही उड्डयन सुविधाओं के बेहतर उपयोग और यात्रियों व माल परिवहन के लिए बेहतर हवाई यात्रा सेवाएं देने के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। इस नीति के लागू होने से प्रदेश में उड्डयन के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने तथा यात्री व कार्गो कनेक्टिविटी में सुधार का नया मार्ग प्रशस्त हुआ है। नीति के तहत पहले चरण में बाड़मेर में उत्तरलाई, उदयपुर हवाई अड्डे के उन्नयन के लिए कार्य किये जाएंगे। इसके अतिरिक्त सवाईमाधोपुर में चकचैनपुरा, नागौर, भीलवाड़ा के हमीरगढ़, सिरोही के आबूरोड़, तथा श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटान हवाई पट्टियों के विकास के कार्य भी किये जाएंगे।राज्य सरकार ने एयरोस्पोर्ट्स गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हवाई पट्टियों की भूमि को लीज पर उपलब्ध कराने की शर्तों को भी मंजूरी दी है। इस पहल से एडवेंचर स्पोर्ट्स, पर्यटन और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।नागरिक उड्डयन के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए उड़ान प्रशिक्षण संगठन, विमान अनुरक्षण इंजिनियरिंग प्रशिक्षण संगठन, रख-रखाव मरम्मत व ओवरहॉल संगठन की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में झालावाड़ में उड़ान प्रशिक्षण संगठन की स्थापना की जाएगी।

शहरों को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी

राज्य के महत्वपूर्ण शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए भी सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। जयपुर से उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को छोटे विमानों के माध्यम से जोड़ने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इस आंतरिक कनेक्टिविटी से व्यापार, प्रशासनिक पहुंच, चिकित्सा सेवाओं और पर्यटन को विशेष लाभ मिलेगा।

जयपुर, उदयपुर और उत्तरलाई हवाई अड्डों का विस्तार

राज्य सरकार द्वारा राजधानी जयपुर में उड्डयन सुविधाओं के विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 12,778 वर्गमीटर भूमि राज्य सरकार को आवंटित की गई है, जिस पर नया स्टेट हैंगर और वीआईपी परिसर बनाया जाएगा। वहीं उदयपुर हवाई अड्डे के विस्तार हेतु 145 एकड़ निजी भूमि का अधिग्रहण प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त उत्तरलाई हवाई अड्डे पर नागरिक एन्क्लेव और पहुंच मार्ग के लिए लगभग 63 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी जारी है।

स्वामी और प्रकाशक रमाकांत गोस्वामी एवं मुद्रक ताराचंद कुमावत द्वारा महारानी प्रिन्टर्स, 17 मां वैष्णो देवी नगर, कालवाड़ रोड़ जयपुर छपवाकर/मुद्रित कर, 10 MA, आईजी नगर, जगतपुरा,जयपुर, राजस्थान - 302017 से प्रकाशित किया। संपादकः रमाकान्त गोस्वामी, पीआरजीआई नं. RJBIL/25/A1815 ब्रांच ऑफिसः 18k3, पंकज सिंघवी मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर-302002, मो. नं. 7610866001, हैल्प लाईन नं.: 8946840063, ईमेल आईडीः tasneemtv.official @gmail.com, वेबसाइटः www.tasneemtv.com (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी. आर. पी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तदायी), किसी भी वाद-विवाद से निपटने के लिए न्यायालय जयपुर मान्य होगा।